12.36 hrs.

CONSTITUTION (FORTY FIFTH AMENDMENT) BILL.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक नहीं हो रही है और न ही उस को गठित किया गया है । इस पर कितना समय रखा गया है ? चूंकि हम लोग भी अपनी तरफ से नाम देना चाहते हैं.....

अध्यक्ष महोदय : मैं बता रहा हूं...

The House will now take up the Constitution (Forty-Fifth Amendment) Bill, 1980. I think that two hours will be sufficient for all the three stages of the Bill

If the House agrees, we may have one hour for the General Discussion and one hour for the Clause-by-Clause consideration and also for the Third Reading. There is paucity of time and all hon. Members on both sides of the House, I think, will feel the necessity because, before 26th, we will have to do it. That is why I am putting it to you.

श्री सूरज भान (अम्बाला) : अध्यक्ष महोदय, इसे बिना किसी डिस्कशन के पास कर दिया जाय ।

MR. SPEAKER: If the House agrees it is all right; but the matter has to be formally put and carried.

श्री सूरज भान : मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं । बगैर डिस्कशन के यह जरूर पास किया जाय, लेकिन एक बात ध्यान में रखी जाय कि बिल के यहां पास होने के बाद लाजमी तौर पर स्टेट्स से इस का रेटिफिकेशन हो ।

अध्यक्ष महोदय : वह अपने आप हो जायगा ।

श्री सूरज भान : ऐसा नहीं है। अखबारों में कुछ दूसरी चर्चा चल रही है ।

MR. SPEAKER: Let us cross the bridge. It would take less than 2 hours. So, please make a move.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना): अध्यक्ष महोदय, रूल 377 के तहत आल इण्डिया रेडियो के गलत प्रचार के बारे में मैंने एक नोटिस दिया है । मालूम नहीं उस का क्या हुआ ?

MR. SPEAKER: We have allowed already five Members under Rule 377. Now please sit down.

SHRI SAMAR MUKHERJEE (Howrah): I wish to make a submission that we will support the Bill and no doubt the Bill will be passed unanimously. But some time should be given to place some points of view.

MR. SPEAKER: That is what I have already said.

SHRI SAMAR MUKHERJEE: One or two hours would be insufficient.

MR. SPEAKER: Let me see the feasibility.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Sir, we know how the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes had been looked after during the past thirty years. That must be fully exposed. Both the people and we know how good you had been to them.

MR. SPEAKER: Don't make a remark like that. Now, two hours have been allotted. Afterwards, it has to go to Rajya Sabha.

गृह मंत्री (श्री ज्ञैल सिंह) : मैं प्रस्ताव* करता हूं :

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

आनरेबल मेम्बर साहबान ने ख्याल प्रकट किया कि बिदाउट एनी डिस्कशन यह बिल पास किया

*Moved with the recommendation of the President.

जावे । तो मैं यही समझता हूं कि इस में और कोई स्टेटमेंट करने की जरूरत नहीं है ।

MR. SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

श्री जयपाल सिंह कश्यप ।

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : इस में कुछ संशोधन दिए गये हैं, उनके बारे में आप क्या करेंगे ?

MR. SPEAKER: That will be done when the amendments are taken up. Now, it is the consideration stage.

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस संविधान (संशोधन) विधेयक पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं ।

पूज्य महात्मा गांधी जी, बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेदकर, श्री पैरियर रामास्वामी नायकर और डा. राम मनोहर लोहिया का यह स्वप्न था कि इस देश के करोड़ों शोषितों और हरिजनों को भी वह सम्मान समाज में मिलना चाहिये, जो सम्मान इस देश के दूसरे लोगों को मिला हुआ है, लेकिन इन के 30 साल के शासन के दौरान भले ही कहने के लिये इन को सुविधायें देने का नाम रहा हो, लेकिन आज भी हरिजन अत्याचारों के शिकार हो रहे हैं। कल ही अखबार में एक घटना के बारे में आया है कि बिहार में एक हरिजन मां और बेटी को जिन्दा जला दिया गया ।

इस देश में आज भी करोड़ों-करोड़ों हरिजनों को मानवता का सम्मान नहीं मिल रहा है चाहे वह आर्थिक हालत हो और चाहे सामाजिक हालत हो । . . . (व्यवधान) इस देश में आज भी वही स्थिति है । 30, 35 साल तक आप की हकूमत रही है चाहे दो, ढाई साल तक दूसरों की हकूमत रही हो लेकिन आप यह देखें कि हरिजनों की समस्याएं उतनी ही विकट हैं, आदिवासियों की समस्याएं भी उतनी ही विकट हैं जितनी कि पहले थीं। आज समाज में उन को कोई सम्मान नहीं मिल रहा है । एक कुत्ता तो चारपाई पर बैठ ले लेकिन एक हरिजन को चारपाई पर बैठने का अधिकार नहीं है । जिस देश में ऐसी हालत हो, वहां पर 10 साल के लिए आरक्षण बढ़ाने की मांग गलत है। मैं तो यह कहूंगा कि कम से कम 30, 35 साल तक के लिए और इस को बढ़ा देना चाहिए । इस देश के अन्दर आज जो कुछ हो रहा है, उसमें यह जरूरी है । आज हरिजनों को उनका हक नहीं मिल रहा है । कुर्सी के स्वार्थ के लिए आप उनको बात कहते हैं लेकिन गद्दी पर बैठ कर हरिजनों का शोषण किया गया है । . . . (व्यवधान) . . जो ये लोग मेरी आवाज को बन्द करने के लिए शोर मचा रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे जा कर उन गरीबों की हालत को देखें । महुआ की रोटी खा कर, घास की रोटी खा कर वे लोग अपना गुजर करते हैं और उनके बच्चों को एक बार भी दूध नसीब नहीं होता है । इस सब के लिए आपका 33 साल का शासन जिम्मेदार है । इस संशोधन के पक्ष में तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि संशोधन आबादी के अनुपात से ही नहीं बल्कि इन के लिए 25 परसेन्ट आरक्षण होना चाहिए । और यही नहीं, कम से कम 25 और 30 साल के लिए आरक्षण होना चाहिए । आज जो इन के साथ व्यवहार हो रहा है, इस आरक्षण से, इस की थोड़ी सी सीमा बढ़ाने से, हरिजनों की समस्याओं का समाधान आप नहीं कर पाएंगे। आदिवासियों की समस्याओं का समाधान यह नहीं कर पाएगा । इस देश में करोड़ों करोड़ों मल्लाह, केवट, कहार, धीवर, निषाद आदि समाज के वे लोग भी रहते हैं जिनकी हालत आज इन हरिजनों से भी बदतर है, जो बेचारे नदियों के किनारे रहते हैं, समुद्र के किनारे रहते हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पिछले 30 सालों में सरकार ने उनको कोई स्थान दिया है, कोई सुविधा दी है । आप जरा ठंडे दिल से इन करोड़ों-करोड़ों मछुओं के बारे में सोचें, जो पानी में खेती करते हैं । तुमने उनके जीवन, उनकी जिंदगी की आर्थिक अवस्था सुधारने के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ी ।

इस देश में करोड़ों दस्तकार हैं, नाई हैं, बढ़ई, लुहार हैं और लोग हैं। वे गरीब दस्तकार हैं और बहुत अधिक संख्या में हैं। लेकिन गरीब होने की वजह से वे यहां नहीं

[श्री जयपाल सिंह कश्यप]

आ सकते हैं। उन कुम्हार से लेकर, गड़ेरियों से लेकर जो भी दस्तकार हैं, सभी को आरक्षण में लाया जाए ताकि वे भी चुन कर यहां आ सकें । इस लोक सभा में आ सकें, देश के प्रांतों की विधान सभाओं में आ सकें ताकि उनका जीवन भी सुधर सके ।

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur): Mr. Speaker, Sir, on behalf of the CPI(M), I welcome the Constitution (Forty-Fifth) Amendment Bill, 1980 which seeks to amend Article 334 of the Constitution.

Even after thirty years of Congress rule and 2½ years of Janata rule, the plight of the scheduled castes and scheduled tribes has not improved as we envisaged and expected. In this connection, I would also like to mention that some ways and means should be found out so that the scheduled castes or scheduled tribes who have converted themselves as neo-Budhists or have embraced Christianity or Islam are also treated as scheduled castes or scheduled tribes and they are not deprived of the benefits due to them. These scheduled caste persons work in big cities like Delhi, Bombay, Madras and Calcutta as also some other towns and keep these places clean, but it is unfortunate that they do not get human treatment from the society and from the nation. Most of the scheduled castes and scheduled tribes live in the rural areas and they are agricultural workers and share-croppers. About 95 per cent of these people live below the poverty line. It is our duty to devise ways and means to help their economic upliftment and we should have a proper social and human approach to solve their problems. One of the ways is that we must implement land reforms properly. In my State, where there is a Left-Front Government, they are implementing land reforms properly and they have passed one legislation that share-croppers' rights should be recorded and their eviction should be stopped. Just before elections Shri Bhola Paswan Shastri visited West Bengal and he, who is a true Gandhian, said that West Bengal was properly implementing land reforms and that they had given rights to the share croppers and agricultural labourers. Actually, this is the State which has served properly the scheduled castes and scheduled tribes.

Then, there is another important matter. Namashoodras in West Bengal are treated as scheduled castes, but in Bihar and U.P. they are not. Similarly, Sunri community in West Bengal is treated as scheduled castes, but in Bihar in Dhanbad and Santhal Pragana, they are not even these people working in Chittaranjan Railway workshop are not treated as Scheduled Castes. In Gujarat, Bihar and U.P. there are many communities who are treated as scheduled castes or scheduled tribes, but in Assam and other States they are not. It is very essential that some uniform pattern should be followed throughout the country. Any community treated as scheduled caste or scheduled tribe should be treated similarly in the whole of India. In this connection, I want to mention that in the last Lok Sabha, one amending Bill was brought before the House to include and exclude certain Scheduled Caste communities. But before that Bill was passed, the House was dissolved. So, I request the Government that Bill should be brought again before the House, so that the difficulties of the SCs and STs may be removed.

With these words, I support the Bill.

SHRI KUSUMA KRISHNA MURTHY (Amalapuram): At the outset, let me congratulate the Government for realizing the need for bringing in this important constitutional Bill in such a speedy manner. The original provision is this: "The provision relating to the reservation of seats for the SC and ST either in the House of the People or in the Legislative Assemblies of a State shall cease to have effect after the expiration of 10 years from the commencement of the

Constitution." Even before incorporating this provision in the Constitution, some amendments were moved then itself, to the effect that this provision of reservation shall cease to exist, provided the people for whom seats in the legislatures have been reserved, are brought to the level of other advanced classes of people, educationally, socially and economically.

The basis for moving such amendment was the social backwardness of these people. Their backwardness was frozen. These people have been suffering for centuries due to this social backwardness.

When this subject of reservation was discussed in the Constituent Assembly, many hon. Members started saying that the 10-year period was quite inadequate, when compared to their backwardness. In reply thereto, our beloved leader, Late Pandit Nehru made a pertinent observation in that connection, by saying that "it was not inadequate if the leader of this country put their heads together to bring them up."

Thus it was made very clear that the passing of the enactment alone was not sufficient. There must be a basic change in the hearts of the people who matter on this issue. That has been made very clear on the floor of this House by Late Pandit Nehru. Later, while disallowing all the amendments, Dr. Ambedkar made it very clear and he emphatically said:

> "If at the end of 10 years, the SCs find that their position has not improved or that they want further extension of this period, it will not be beyond their capacity or their intelligence to invent new ways of getting the same protection which they are promised here."

It is clear that the scope for getting this safeguard extended was not ruled out; and it is also very clear that the option of demand for this extension is given to the people for whom this safeguard is meant. Therefore, while initiating the discussion during the first amendment of this constitutional provision in 1959, for another 10 years, the then Home Minister, Shri Govind Ballabh Pant, made it very clear on the floor of this House that the reasons which weighed with, and influenced the Constituent Assembly for making this provision for reservations, did not cease even then.

Therefore, I feel that the same reasons which made the Constituent Assembly pass this Bill and also again extend this provision still hold good, in the sense that the purpose for which the provision was originally enacted in the Constitution, has not yet been achieved. Everyone of us knows that our approach to this grave problem of social evolution in India is drawing the attention of the whole world. We are so practical and practicable in our ways and means to bring about a social evolution of such an unimaginable magnitude. Our approach is peaceful, silent and democratic in all respects; and it was evolved under the dynamic leadership of our beloved leader Pandit Nehru.

If this social transformation is not brought about through constitutional means in this country, the country has to face a "caste war" unlike in other countries which faced "class wars" during the course of history. Therefore, in this connection, though we all wanted to have a casteless and classless society, we are not able to achieve this because of so many of our inherent inhibitions; and that is why we have brought forward this Bill again today in Parliament.

I can cite many examples from the 24. Reports of the Commissioner of SCs and STs which have elaborately and clearly mentioned their humiliations, suppressions and denial of civil rights even till today. Even after providing this clause, they have not come up to the expected level. There

[Shri Kusumakrishna Murthy]

are Elayaperumal Committee, Shilu Ao Committee, and the Parliamentary Committee for the welfare of SC & ST besides so many other provisions in the Constitution and in spite of all that, the expected results we have not been able to achieve because the implementation of those provisions is not being properly done. Therefore, in this connection, I would request the Government not only to see that the amendment is passed but also to see that the provisions are properly implemented by creating a separate Ministry at the Centre. In various States, we know that there are separate Ministries for Harijan upliftment. In the Centre also if such a Ministry is there, they can exclusively look after this matter and see that the provisions are properly implemented. Secondly, in order to get the utility of these safeguards properly extended to the really deserved, the government must immediately see that the lists of the SC & ST are properly and objectively revised.

Therefore, the Government while bringing forward this amendment must also bear in mind Article 46 in Chapter 4 containing the Directive Principles which says: "The State shall promote with special care the education and the economic interests of the weaker sections of the people and in particular all the SCs and STs and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation." Therefore, would it be proper for a civilised society to deny the just claims of those suppressed and oppressed people who have been suffering for centuries together? In this context I would like to be very clear that a period of 10 years or 30 years is absolutely of no consequence because the magnitude of the problem of their suffering for centuries together is such that we will not be able to wipe out these sufferings in a short period. Therefore, the amendment moved in the beginning, I think, is bound to operate and these safeguards are bound to continue until these classes are brought up actually into the main stream of life and also to the level of all those advanced classes of people in our society.

MR. SPEAKER: Shri Bapusaheb Parulekar.

श्री जैल सिंह : स्पीकर साहब, आज जितना टाइम अलाट किया है उसमें से सारा का सारा टाइम न चला जाये। मैं रिक्वैस्ट करूंगा कि बाबू जगजीवन राम जी जरूर इसमें कुछ कहें।

MR. SPEAKER: He is not present. I have to inform the House that voting on the motion for consideration of the Constitution (Forty-fifth Amendment) Bill will take place at about 3 p.m. Thereafter voting on the clauses and motion for passing the Bill will be held at the appropriate time. Now we adjourn the House for lunch to meet again at 2 p.m.

13 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

—

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

CONSTITUTION (FORTY-FIFTH AMENDMENT) BILL—*Contd.*

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR (Ratnagiri): Mr. Speaker, at the outset I thank you very much for having given me this opportunity to speak though my turn had already gone. In supporting this Bill generally, I should like to make a few submissions by way of suggestions to the hon. Minister and the Government. Everybody knows that the safeguards by way of Article 334 in the Constitution were introduced because of low educational and economic conditions of the Scheduled

Castes and Tribes people. Before the appointment of the constitution committee and the Constituent Assembly, an advisory committee for making recommendations on minorities was created and that committee submitted a report on 8th August, 1947 and that report went very much with the Constituent Assembly. With reference to that particular report this Article 334 came to be enacted in the Constitution. That report mentions, *inter alia*:

> "It is on account of the extremely low educational and economic conditions of the Scheduled Castes and Tribes and the grievous social disabilities from which they suffer that political safeguards and reservation of seats had to be granted to them."

It is really unfortunate that in the last 33 years we were required to amend this article twice and this is the third time that we are required to amend this particular article. It shows that all the governments were not in a position to fulfil this pledge to improve the conditions of the Scheduled Castes and Tribes people. Under the circumstances, though you, I would like to ask the Government and the hon. Home Minister as to whether they really believe that in the next ten years, the period now mentioned in the amendment, the economic and educational conditions of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are going to be improved to such an extent that there will be no necessity of the political safeguards in future. I would also ask through you to the hon. Minister as to whether they really believe that the grievous social disabilities under which these classes of people have been suffering for thousands of years will be removed in the coming ten years. If so, whether he will give a guarantee to that particular effect.

I would like to invite the attention of the hon. Minister to one other important point to which a reference was made by my colleague Shri Halder and I had also referred to that in my speech on the Scheduled Caste Order in the Sixth Lok Sabha. As far as the Neo Buddhists are concerned, they are not governed by the definition of Scheduled Castes. At the time when Article 334 came to be enacted, they had not embraced Buddhism. They have not improved their educational and economic conditions. Therefore, I would request the hon. Minister and the Government to give considerable thought to this particular aspect. The usual argument that is placed before us is Clause 3 of the Scheduled Castes Order. Section 3 was *inter alia* mentioned to quote—

> "notwithstanding anything contained in paragraph 2, no person who professes a religion different from Hindu or Sikh religion shall be deemed to be the Member of the Scheduled Caste."

In all Acts and in all legislations we have defined 'Hindu' to mean and include Buddhists and Sikhs. There is no logical argument. I would, therefore, appeal to the hon. Home Minister and the Government, as the social, economic and financial condition of those people who have been converted, to Buddhism from Scheduled Castes have not improved, they should also be included in this Article 384.

I would also like to invite attention of the hon. Minister to Clause 334(b). I fail to understand as to what is the useful purpose in giving this facility and protection to the Anglo-Indians. They are sophisticated, cultured, intelligent rich people. In the year 1950 or 1952 when the Constitution was written, it would have been all right. In the present circumstances I would request the Government to give a serious thought as to whether Article 334(b) should be there.

Lastly, I would invite the attention of the hon. Minister to see whether

[Shri Bapusaheb Parulekar]

there should be nomination as far as the Anglo-Indians are concerned. Why is there discrimination between Anglo-Indian and Harijans? Anglo-Indians can also be asked to contest and come and not that one person may continue as a Member for forty years. If we ask them to contest, other Anglo-Indians may also come.

MR. SPEAKER: Shri Thazhai Karunanithi.

SHRI THAZHAI KARUNANITHI (Nagapattinam): (*Spoke a few words in Tamil*)

SHRI AMAR ROY PRADHAN (Cooch Behar): There is no interpretation.

MR. SPEAKER: The interpretor is, at the moment, not present. Mr. Karunanithi, please wait. Shri Buta Singh.

SHRI BUTA SINGH (Ropar): Mr. Speaker, on behalf of the millions of Indian masses, known and listed as Scheduled Castes and Scheduled Tribes of India, I take this opportunity to congratulate Shrimati Indira Gandhi, the doyen among those who champion the cause of the socially depressed and economically down-trodden people of India, for bringing forward this piece of legislation as a first promise that she made to the people of India in the last election. This is an occasion where we should not have brought in factional politics while discussing this piece of legislation. But unfortunately, the opening Speaker started making some charges against the Congress Party which are wholly uncalled for. The Speaker who preceded—Mr. Parulekar —also questioned the Congress Party's intention while implementing the measures during the last 30 years. It is indeed an occasion where the entire nation stands behind and appreciates this measure of social reform brought by the present Government. A point has been made by two hon. members, namely, Mr. Halder and Mr. Parulekar, that those from among the scheduled castes and scheduled tribes who have embraced Buddhism and Christianity should be treated and enlisted as scheduled castes and scheduled tribes. We are all in sympathy with this demand. There is no doubt that after embracing a particular religion, one does not get economically and educationally emancipated. As Mr. Parulekar himself read out, the main ground, the basis of the very idea of bringing this legislation either today or in the first instance was the most grievous social disabilities from which these people were suffering and continue to suffer today. Unless these grievous social disabilities are removed and these people are brought at par with the other sections of the Indian masses, it will not be justified and it will be something injurious to the welfare of these people that we do not attend to our duties which are given in the Constitution itself, namely, that the State will take special care in promoting the welfare of the weaker sections, especially the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. No doubt those who have embraced Buddhism and Christianity do suffer from the same economic and educational backwardness. But Mr. Parulekar took special care to advocate the cause of the Buddhists only. He did not say a word about those who have become Christians. My contention is that in some States like Maharashtra, Kerala and others where people have embraced either Buddhism or Christianity the State Governments have evolved some measures through which they are catering to the needs of those who have converted themselves. But so long as the philosophy of casteism remains in the society and so long as the people are continued to be treated as socially degraded people on the basis of caste, I am afraid those religions who do not believe in or who do not profess the theory or philosophy of casteism could not have been and cannot be considered through the present measure. So, to that extent this question becomes irrelevant as far as the Constitution of India as it exists today goes. We have our sympathy for them and I would urge on the Home Minister to sit with

the State Governments and find out some way through which the State Governments as well as the Central Government can do something for those weaker sections who have embraced those religions.

This question of extending the reservation beyond the sanctioned period provided in the Constitution has been hanging fire for sometime past. It is indeed a matter of a little concern for us today that it was left only for the Congress Party to have taken this measure and come to the aid of these people. What was happening during the last 29 months?

Some of my friends sitting on this side of the House have been criticising the Congress Government for 30 years, but they conveniently forgot the last 30 months. What was happening to these people during the last 30 months? What was the Government doing, whether it was the Janata Government or the Lok Dal Government? Those who have been known as the champions of the downtrodden people have been keeping silent. They did not move a small finger. Our sisters, our mothers and our brothers were burnt alive. Day in and day out atrocities were increasing. Not a word came from those so-called self-styled leaders of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes enjoying the high offices both in the Janata Government and in the Lok Dal Government, so much so a serious attempt was made, I should say, deliberately with a political motivation by the Lok Dal Government to see that this measure becomes redundant, that this date passes.

I am really grateful to Shrimati Indira Gandhi for having brought this measure as the first measure from her government to ameliorate the downtrodden people of India.

One word, and I have done. It was a wrong notion in the country that only the people, the big leaders belonging to certain sections could best represent the interests of those sections. A lot was said about kisans, much was said about Harijans. But today the people of India by and large and the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in particular. have given a telling verdict saying that Shrimati Indira Gandhi is the only leader of the weaker sections and their interests are safe in her hands.

Sir, what was done in the name of fair elections? Who were the victims during the last elections? Not the high castes, but the weaker sections, the backward classes and especially the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. I can name the constituencies in this country where the poor Scheduled Castes are denied the right of exercising their franchise even today. Is it not a fact?

With these words, I offer my heartfelt support and congratulate the Home Minister and the Prime Minister for bringing this piece of legislation which will go a long way to ameliorate the underdogs, the downtrodden people, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

There are certain things which the Home Minister should immediately attend to. There are certain tendencies growing in the country in the name of anti-Scheduled Castes and anti-Scheduled Tribes. There are regular agitations going on in a few States, of course encouraged by the communal and the sectional factions of the power politics in the States. I would request the hon. Home Minister to take a serious note of it because these concessions have constitutional sanction. They are provided in the Constitution of India. Anybody opposing these concessions to the weaker sections should be treated as anti-national and they should be treated as those who are opposed to the very idea of attending to the problems of the weaker sections.

[Shri Buta Singh]

In the matter of Services, I will come to that when an opportunity comes, but having had the opportunity of heading a Parliamentary Committee for three years, I have some little experience. Let the Government take a very serious note of all the reports that have been produced by the Parliamentary Committee on the subject and also go in depth through the reports of the Scheduled Castes Commissioner so that the Government will be in a real position to do something for the people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

*SHRI THAZHAI KARUNANITHI (Nagapattinam): Hon. Mr. Deputy Speaker, Sir, at the very outset I would like to express my gratitude to my beloved leader Dr. Kalaignar Karunanidhi and the people of my constituency who have given me this grand opportunity to make my maiden speech on the floor of this august House.

I would like to say on behalf of Dravida Munnetra Kazhagam that we are all grateful to Shrimati Indira Gandhi, our Prime Minister, who has introduced this 45th Constitution (Amendment) Bill. It is only appropriate to recall that a decade ago it was during the enlightened rule of Shrimati Indira Gandhi that the reservation, for the scheduled castes was given statutory support. Now it has again been left to her to introduce this Constitution Amendment Bill which seeks to extend the reservation for them.

There cannot be any dissent from any quarters of this House that the scheduled caste people should get the reservation because then alone the centuries-old economic and social backwardness can be eradicated. Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru and Ambedkar and many other illustrious sons of India like Thanthai Periar, Arignar Anna and Dr. Kalaignar Karunanidhi who has been relentlessly waging a war on untouchability following the footsteps of the two eminent sons of Tamil Nadu have all been concerned with the woes and wails of these unfortunate children of mother India. The country has got freedom, but these people have not yet been freed from their economic and social slavery. They are treated worse than the dogs and pigs. It is ironical that while the dogs and pigs are patted with paternal affection these human beings are kept at a distance from upper class people. Their trials and tribulations can be ended if this reservation with statutory support becomes a permanent feature; this reservation should not become a mercy in the hands of authority. To give an example, there is reservation of jobs for these people in the Government and public sector; but there is no such job reservation in the private sector. How do we expect to eliminate their economic dependence if we do not ensure job reservation in all the services? If a scheduled caste candidate embraces Islam, he can become a Maulana; if a scheduled caste candidate joins Christianity, he can become a Father. But in Hinduism he cannot become a temple *poojari*. During his chiefministership, Dr. Kalaignar Karunanidhi removed this disability of these people through law providing that scheduled caste people can also become temple *poojaris*. I take this opportunity to appeal to our Hon. Prime Minister that this law should become universal throughout India; it should become a central law.

With these few words, I conclude my speech thanking the Chair for the indulgence shown towards me.

SHRI P. K. KODIYAN (Adoor): I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on this very important subject.

*The original Speech was deliver ed in Tamil.

I think the entire House is in agreement with the proposed amendment. The reason for the founding fathers of our Constitution providing special safeguards for the scheduled castes and scheduled tribes still exists, namely their social backwardness. In the last 30 years several things have been done by the Government, I do not deny it, but these things have not brought about any basic improvement in their living standards and their social status. I need not explain the various difficulties which are confronting them even today.

Everybody knows that the scheduled castes are subject to social oppression even today. Even social boycott is sometimes imposed on them. For days together they are not allowed to draw water and the shopkeepers are asked by the upper caste people not to supply even foodgrains to the scheduled castes with the result for days together they are forced to starve. One important criterion for determining the social backwardness is the prevalence of the practice of untouchability, whether they are suffering from that stigma. Even though there has been improvements in the urban areas, by and large, the practice of untouchability still continues in our country.

Education has provided them some better facilities of life, but those who have been covered by these educational facilities are a microscopic minority among the vast masses of the scheduled castes and tribes. Even the educated people sometimes do not get proper accommodation and they are being discriminated against in this respect when they are transferred to distant areas, particularly in the rural areas.

The most important aspect of improving the living conditions of the scheduled castes and scheduled tribes is to provide them with means for economic self-reliance and providing them land. The bulk of them are landless, and the tribal people have lost their land to money-lenders and other vested interests. So far as the tribals are concerned, though many of the States have passed laws for restoration of land to them, nowhere it has been implemented. I would like to draw the attention of the Home Minister particularly to this aspect. The tribals are being pushed more and more to the interior of the forest areas and they are losing their land. So far as the Harijans are concerned, it was expected that as a result of the implementation of land reforms a considerable number among them would be provided with land. But the implementation of land reforms in our country was very very unsatisfactory. So that expectation also has been belied. The bulk of these people, whether they are Harijans or tribals, are agricultural workers and...

MR. SPEAKER: Please conclude. You were allotted only two minutes, and you have already taken five minutes.

SHRI P. K. KODIYAN: Let me complete this point. Though the States have passed laws fixing their minimum wages, it has not been implemented. I would request that this should be implemented. I agree with Shri Parulekar and Shri Buta Singh that this concession should also be extended to those who get converted into other religions *viz*, Buddhism and Christianity.

SHRI C. CHINNASAMY (Gopichettipalayam): Mr. Speaker, Sir. I, on behalf of All India Anna DMK Party welcome this Bill and extend my full support to the Constitution (Forty fifth Amendment) Bill, 1980.

This measure has come at the most opportune moment. I am extremely happy to note that this Bill carries out what my respected Leader, Thiru M.G.R. has cherished all along, that the special statutory provisions in respect of the Sscheduled Castes and Scheduled Tribes should continue.

[Shri C. Chinnasamy]

In fact my party and the party Leader have taken a decision to reserve seats even in local body elections, which was hitherto unthought of by any political party in India.

With these words I conclude my speech.

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : स्पीकर साहब, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने की इजाजत दी।

34 साल इस देश में कांग्रेसी हकूमत रही । इन 34 सालों में हरिजनों को इतना मिला कि अभी तक वे आजादी के साथ वोट नहीं डाल सकते हैं । मैं आपको पंजाब की हालत बताता हूं । लेण्ड रिफार्म्स न होने की वजह से वहां जमीन बड़े जमींदारों के पास है ।

मैं हरिजनों को कहूंगा :

Nobody can get his rights by request, rights are wrested from unwilling hands.

जब तक आप डट कर मुकाबला नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा ।

मैं मांग करता हूं कि इसको जल्दी से पास किया जाए।

मेरी अब जिन्दगी को ठोकरें खाना नहीं आता,
मैं मजबूरे तमन्ना हूं कि मर जाना नहीं आता ।
तेरी बज्म में आ कर हमें जाना नहीं आता,
हवासोहोश खो कर दिल को समझाना नहीं आता ।

हम ही तो इसके मालिक हैं,
कोई बेगाने के घर में बेगाना नहीं आता ।

तेरे मस्तों को साकी शोरे महशर क्या उठाएगा
ये वो हैं जिन को पी कर होश में आना नहीं आता ।

SHRI CHITTA BASU (Barasat): Sir, I take this opportunity to support the Bill which seeks to extend the period of reservation for another ten years for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Anglo-Indian communities. Before we extend our support, I would urge upon the hon. Home Minister to make a correct reappraisal of the conditions of life and work of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in our country. If you allow me, Sir, I would just bring to your kind notice the observations made in the Twenty-Fourth Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, it is a horrible tale told by the Commissioner:

> "They continue to submit to the decrees of fate rather than have the benefits of the decrees of our basic law. Liberty, Equality and Fraternity, so richly enshrined in the Constitution of the country have still to acquire any meaningful proposition for most of them....."

It further goes on to say:

> "The nation's resolve made with due solemnity to secure to all the citizens 'Justice—Social and Economic' has remained just a promise, honoured perhaps more in breaches in the case of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes."

Therefore, I would urge upon the hon. Home Minister to really understand the sense of frustration and disappointment caused to them, as has been revealed in the Twenty-Fourth Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. If we make a correct reappraisal of the situation in our country, particularly in regard to the condition of life and work of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, it will be a horrible profile for us to see. The number of persons living below the poverty line has been increasing day by day. It is estimated that in the urban areas, 55 per cent of the population and in rural areas 50 per cent of the population are living below the poverty line. Most of the Scheduled Caste and Scheduled

Tribe people belong to this category of people living below the poverty line.

You would also agree with me that bondage exists even today, even after three decades of our independence. Among many forms of exploitation of the Schedued Castes and Scheduled Tribes is one which forces them to work as bonded labour.

There is a steep fall in the enrolment of Scheduled Caste students in Classes V to VIII, and this trend continues right upto higher education. Government's assistance is inadequate. This will be proved by the fact that only three lakh students belonging to the Scheduled Castes were in receipt of Government of India Post-Matric Scholarship in 1976-77. The progress of education is not very much satisfactory particularly among the Scheduled Tribes in our country.

I will mention only one point more. If you see the comparative figures in respect of education, particularly the literacy rate, you will find that, among the tribal communities, the literacy rate in 1971 had gone down as compared to 1961. This is a very revealing fact. In fact, there are certain tribal communities who are at zero level of literacy. The comparative data about rate of literacy during 1961 and 1971 show that, in the States of Andhra Pradesh, Assam, Bihar; etc.; there has been generally a decline in the literacy rate.

I only want to remind the hon. Minister of the speech made by Dr. Ambedkar. As a matter of fact, he was not in agreement with the reservation proposal for ten years when the Constituent Assembly was debating this. I am really surprised to know whether the Government has come to this conclusion, as my friend, Dr. Parulekar was saying, that the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes will be brought on par with the vast masses of our people unless some economic assistance is given to them within this period of ten years and whether it is necessary to have a consideration of that point also.

SHRI P. M. SUBBE (Sikkim): Thank you very much for the opportunity you have given me.

I am representing Sikkim and Sikkim is the last State which had joined the mainstream recently. So it is the youngest State at the national level. I would earnestly request that if possible, special consideration should be given to my State. It is a very backward State, backward in all respects— economically, politically and educationally. Over and about that, the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people are very much downtrodden and they are educationally backward. At the officer level you will find they are very meagre in number. So, if all our friends agree, the maximum facilities may be extended to Sikkim also.

SHRI FRANK ANTHONY (Nominated-Anglo-Indians): I did not wish to say anything except to thank the Prime Minister and her government for having brought in this amending Bill extending the period and also the other groups and parties for having generally supported this extension.

I only want to reply very briefly to Mr. Parulekar who questioned the need for continuation of the facility of reservation for the Anglo-Indian community as they are an intelligent and well-to-do community. He wanted Anglo-Indians to contest elections in the way the Scheduled Castes do. Here I just want to say this.

Not many members know how I secured this, provision. I had the blessings and the support of Gandhiji. I told him the special difficulties of my community. He lent me a powerful support and in appreciation of that he said 'Although relatively you should not get many seats but he gave me an assurance of not one, not two but three seats in the Constituent Assembly'. Jawaharlal Nehru and Sardar Patel and particularly, the Chairman of the Advisory Committee on Minority Rights gave me special and very powerful support.

[Shri Frank Anthony]

Now, Mr Speaker, you may not remember the original decision. The original decision was to give all the minorities reservation in the context of General Electorates as was done for the Scheduled Castes. But then Gandhiji was murdered and the whole matter was thrown back into the melting pot and the reservation for the minorities was withdrawn. I submitted my case again and this is what Jawaharlal Nehru and Sardar Patel said—I reproduced it in my book:

> "The case of the Anglo-Indians presents special difficulties, not because they are a backward class but because of certain historical and other reasons. The special safeguards and the safeguards of the Scheduled Castes will remain intact."

But Sardar Patel categorically said why it could not be in the background of an election.

> "We cannot give them this reservation....I am quoting him:
>
> ...In a General Election which is meaningless. They are too small, too scattered. We cannot give them representation in the Upper House. If we have to give them effective representation, it will have to be in the lower House by nomination."

I am grateful for the tribute that we are an intelligent community which contributed out of proportion to its size in the wars with Pakistan, but we are not a wealthy community. There is acute unemployment in my community and my estimate is that between 35 and 50 per cent of the community to-day is unemployed.

श्री अरविंद नेताम (कांकेर): अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। सर्व प्रथम मैं प्रधान मंत्री और गृह मंत्री को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि यह विधेयक ठीक समय पर पेश किया गया है।

जहां तक आरक्षण के समय को और दस साल बढ़ाने का सम्बन्ध है संविधान के निर्माताओं ने इस देश के शिड्यूल कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज को ये सुविधायें दी थीं। जब भी इस प्रकार का विधेयक सदन में आता है तो हमेशा यह पूछा जाता है कि इस बात की क्या गारण्टी है कि दस सालों में इन लोगों का आर्थिक और शैक्षणिक विकास हो जायेगा। मैं इस देश के लोगों को और खासकर समाज के उच्च वर्ग को कहना चाहता हूं कि अगर सब लोग अपनी भावनाओं को बदलें और दिल से चाहें कि ये दोनों पिछड़े वर्ग आगे बढ़ें तो मैं समझता हूं कि इस रिजर्वेशन और प्राथमिकता देने की जरूरत नहीं होगी।

माननीय सदस्य श्री बूटा सिंह ने कहा है कि इस देश में कुछ ऐसे तत्व हैं जो इसका विरोध करते हैं। उनके विरोध का कारण तो समझ में नहीं आता है, लेकिन यह बात सही है कि जिन जातियों पर सैकड़ों हजारों सालों से ज्यादतियां हुई हों यह असम्भव है कि सिर्फ बीस तीस सालों में उन सब की उन्नति हो जाये उनमें जाग्रति आ जाये। इस लिए मैं चाहता हूं कि समाज के अन्य लोग उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सहयोग दें। जब तक वे ऐसा नहीं करेंगे तब तक महज़ सरकार की सहायता से वे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। किसी भी वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए समाज के दूसरे वर्गों के सहयोग और सहायता की आवश्यकता होती है। मैं चाहूंगा कि इस देश के लोग इन वर्गों को आगे बढ़ाने में मदद करें।

मैं गृह मंत्री महोदय से यह बात खास तौर पर कहना चाहता हूं कि यह देखने में आया है कि बहुत से आदिवासी क्षेत्रों में दूसरे लोगों का काफ़ी संख्या में प्रवेश हो रहा है। इसके कारण आदिम जातियों में जो असुरक्षा या अशांति की भावना पैदा हो रही है, गृह मंत्री महोदय उसकी ओर विशेष ध्यान दें। मैं दूसरे लोगों के आदिवासी क्षेत्रों में जाने का विरोध नहीं करता हूं लेकिन सब से बड़ी बात यह है कि आदिम जाति के लोग उनके आने की वजह से असुविधा और असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। गृह मंत्री महोदय जानते हैं कि इसके कारण बहुत से आदिवासी क्षेत्रों में खासकर ईस्टर्न स्टेट्स में कई समस्यायें उठ रही हैं इसलिए वह इस बात का विशेष खयाल रखे। ये, बहुत सेन्सिटिव एरियाज़ हैं इसलिए ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि वहां बाहर के कम से कम लोग जायें ताकि वहां असुविधा और असुरक्षा की भावना पैदा न हो।

मैं एक बार फिर प्रधान मंत्री और गृह मंत्री को बधाई देता हूं कि वह समय पर इस विधेयक को लाये हैं। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*SHRI BAJU BAN RIYAN (Tripura East): Mr. Speaker, Sir, during the last 30 years the Government of India have been formulating various schemes for the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes people but I am to say with a deep sense of regret that not much has been done by way of implementation of these schemes and as a result of this we the Members of the SC & ST communities are lagging far behind the other communities of the country socially, economically and educationally too. Still today we cannot speak in our mother tongue in Parliament or in any State legislatures. So far as employment is concerned only the left front Government of West Bengal have reduced the educational qualifications to help the Members of these communities to get Government service. But I would like to know from the Government whether they or other State Government are going to emulate the example of the Govt. of West Bengal in the matter of giving employment to these people? If the Central and the State Governments were keen for the upliftment of the SC & ST people then surely they could have been benefitted in a big way within less than 10 years time but I have noticed with regret that both the Central and the State Governments had set up many Commissions for this purpose and during the course of time these Commissions had submitted their reports also but regretably enough the Governments did not show enough zeal to implement the recommendations of the Commissions. The Left front Government of Tripura in pursuance of the provisions of the Constitution of India had suggested for the creation of District Councils for the Scheduled Tribes people and our party had fought and agitated for this issue also. We had demanded that not only in Tripura but in other parts of the country also such Councils should be created and more autonomy should be given to the tribal people. But once again it is our misfortune and it is a matter of regret that the Congress Governments particularly the Congress-I Governments had created impediments and even opposed our move. I would expect that the Central Government should atleast not oppose the creation of such Councils.

श्री राम लाल राही (मिश्रिख): अध्यक्ष महोदय, मैं आप को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि सातवीं लोक सभा में एक महत्वपूर्ण बिल पर आज प्रथम बार मुझे आप ने बोलने का अवसर दिया ।

मैंने इस बिल में एक संशोधन पेश किया है और उस में यह कहा है कि संविधान की धारा 334 समाप्त कर दी जानी चाहिए । मैं उस के लिए डरते डरते इस सदन में तर्क पेश करना चाहता हूं क्योंकि हर व्यक्ति ने समर्थन दिया है । मैं ऐसा मान कर चलता हूं कि हमारे हिन्दुस्तान के अन्दर 30 साल की जो राजनीति रही है वह सत्ता की राजनीति रही है । सत्ता के लिए हमने धर्म और जाति के लोगों को संरक्षण और आरक्षण दे कर वोट हासिल करने का प्रयास किया है । अब इस देश के अन्दर अगर इस तरीके की राजनीति चलाई गई और इस तरीके की व्यवस्था चलाई गई तो मैं ऐसा मानता हूं कि न हम देश बदल सकते हैं न समाज बदल सकते हैं और न गरीबी अमीरी की जो महत्वपूर्ण लड़ाई है उस लड़ाई पर हम विजय पा सकते हैं । मैं तो यह चाहूंगा कि इस 334 आर्टिकिल को हटा कर उस की जगह पर ऐसा न्यूनतम आर्थिक आधार रखना चाहिए जिस आधार से नीचे जो लोग हों उन लोगों को लोक सभा और विधान सभा के अन्दर जाना चाहिए । जब तक पिछड़े और गरीब लोग लोक सभा और विधान सभाओं के अन्दर नहीं आएंगे तब तक गरीबों, छोटे लोगों और कमजोर लोगों के लिए यहां पर न कोई कानून बन सकता है और न उस कानून पर अमल हो सकता है । मैं अपनी सरकार से कहना चाहता हूं, हमारे माननीय गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं, देखेंगे संविधान में इसके नीचे जो आर्टिकिल 335 दिया हुआ है क्या उस 335 आर्टिकल की भावना को तीस सालों में पूरा करने का प्रयास किया गया । सरकार में चाहे जो लोग रहे हों वह सरकार चाहे जिस की रही हो मोरारजी भाई की, चाहे चौधरी चरण सिंह जी की, चाहे इंदिरा जी बैठी हों चाहे कमलापति जी बैठे हों, चाहे बाबू जगजीवन राम बैठे हों, चेहरे वही रहे हैं, कुर्सियां बदलती रही हैं, कभी कोई दायें चला गया, कभी बायें चला गया । लेकिन हमारे समाज का जो स्वरूप है उस स्वरूप में कोई ठोस आर्थिक या सामाजिक बदलाव नहीं कर पाये । मेरी दरख्वास्त है इस सरकार से, माननीय इंदिरा गांधी जी से कि अब जाति और धर्म की राजनीति को छोड़ कर उन्हें अमीरी और गरीबी की महत्वपूर्ण लड़ाई को आगे लाना चाहिए जो दो वर्गों के बीच की लड़ाई है । जब देश के अन्दर अमीर और गरीब, इन दो वर्गों की लड़ाई को हम बढ़ायेंगे तब जा कर हम हरिजनों को भी आरक्षण दे सकेंगे, दूसरों को भी आरक्षण दे सकेंगे और ब्राह्मण ठाकुर जो गरीब हैं उन को भी

*The original speech was delivered in Bengali.

[श्री राम लाल राही]

आरक्षण व संरक्षण दे सकेंगे। मैं कहना चाहता हूं, हरिजनों को आरक्षण दिया गया, ब्राह्मण और ठाकुर उस के लिए हम से कहते हैं कि भाई, तुम तो सरकार के दामाद हो। हम को कहते हैं कि तुम तो दामाद हो सरकार के। हमारा नौकरियों में रिजर्वेशन पूरा नहीं है, हम जिला परिषद् की चेयरमैनी के लिए लड़ना चाहें तो नहीं लड़ सकते। क्षेत्र समिति के लिए, क्षेत्र प्रमुख के लिए, प्रधानी के लिए हम नहीं लड़ सकते हैं। यदि हम चुनाव लड़ते हैं तो जाति के आधार पर हम हार जाते हैं। समथन नहीं मिलता। फिर भी कहा जाता है कि हम सरकार के दामाद हैं। तो इस प्रकार की राजनीति नहीं चलनी चाहिए। यहां पर इस सदन में सौ, सवा सौ हमारे हरिजन सदस्य होंगे वे सोचते होंगे कि यह व्यक्ति आरक्षण का विरोध कर रहा है लेकिन मैं जानबूझ कर विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं इस बात को जानता हूं कि अगर आरक्षण और संरक्षण न होता तो मैं यहां कदापि नहीं आ पाता। लेकिन जब मैं यहां पर चुनकर आया हूं तो इसलिए आया हूं कि मैं समाज के लिए कुछ कहूं करूं। मैं चाहता हूं कि जिस समाज के लिए मैं यहां पर चुन कर आया हूं उसके लिए कुछ करूं लेकिन मैं क्या कुछ कर पा रहा हूं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब आप आरक्षण और संरक्षण की बात करें तो उसके पीछे जो मूल भावना है उस पर भी अमल होना चाहिए। इस पर बल दें। जब तक उस पर अमल नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा। अगर उस पर अमल नहीं करना है तो संरक्षण और आरक्षण देने का कोई लाभ नहीं होगा. फिर क्यों दिया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं अब सरकार विचार करे कि आरक्षण व संरक्षण जाति के आधार पर न हो कर गरीबी को आधार मान कर किया जाना चाहिए।

श्री चन्द्र पाल शैलानी (हाथरस) : अध्यक्ष महोदय, भारतीय लोकदल सबसे बड़ा विपक्षी दल है लेकिन आपने केवल एक आदमी को ही बोलने का मौका दिया है।

MR SPEAKER: I have given time according to the strength of the party in the House. I give it according to the time allotted—and even more than that. There can be no objection to it.

श्री चिरंजी चन्द जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए मैं अपने विचार सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। जब हमारी कांस्टीट्एण्ट असेम्बली ने संविधान बनाया था तब दस वर्ष के लिए प्रोटेक्शन दी गई थी। फिर उसको बीस वर्ष किया गया, फिर तीस वर्ष किया गया और अब हम 40 वर्ष करने जा रहे हैं। परन्तु हमें सोचना यह होगा कि जब हम इस प्रकार से बढ़ाते जा रहे हैं तो इसके लिए कोई कार्यक्रम भी बनाना होगा। अब हम दस वर्ष के लिए प्रोटेक्शन बढ़ाने जा रहे हैं तो दस वर्ष के लिए कार्यक्रम भी बनाना होगा ताकि आगे इसको बढ़ाने की आवश्यकता ही न रहे। यदि इसी प्रकार [illegible] बढ़ाते जायें और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग प्रगति न करें, उनकी गरीबी को न मिटा सकें, उनको ऐसी स्थिति में भी न ला सकें कि वे सरपंच और प्रधान के लिए खड़े हो सकें तो इसका कोई वास्तविक लाभ नहीं होगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि देश में जितनी भी बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टीज हैं वह इस बात की कोशिश करें कि जनरल सीट्स पर शेड्यूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब के लोगों को टिकट दें और वे उन सीटों से जीतकर इस सदन में आ सकें। यदि हम इस प्रकार से कोई प्लान नहीं बनाते हैं तो हम संरक्षण को बढ़ाते जायेंगे परन्तु उसके पीछे जो एक उद्देश्य है वह पूरा नहीं होगा। दस वर्षों के बाद फिर यहां पर सरकार को इसको आगे बढ़ाने का कारण बताना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए पहले से ही ऐसी व्यवस्था करे कि आगे से फिर यहां पर आ कर इस संरक्षण को आगे बढ़ाने के लिए कारण न बताने पड़ें।

अभी आप जानते हैं कि छुआछूत का मामला बना हुआ है। आज भी मन्दिरों में हरिजनों का प्रवेश नहीं हो पाता। हमारे राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर के जिलों में मन्दिरों में हरिजनों का प्रवेश नहीं है। इसलिए आपने जो कानून बनाए हैं उनको अमली जामा पहनाना पड़ेगा। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे। पांच वर्ष के लिए यहां पर कांग्रेस (आई) की सरकार बनी है। जनता पार्टी की सरकार ने दस वर्ष का प्लान बनाया था लेकिन वह पांच साल भी नहीं चल सकी। लेकिन हमें विश्वास है कि पांच वर्ष तक कांग्रेस (आई) शासन में रहेगी। पाच वर्षों के अन्दर योजना बनानी चाहिए कि किस प्रकार से हम इन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों की प्रगति करें, विकास करें, उन की गरीबी को मिटायें, जिस से आरक्षण का दस वर्ष बाद अवसर देना न पड़े और हम अपने उद्देश्य में सफल हो सकें।

SHRI U. H. PATEL (Bulsar): (Spoke a few words in Gujarati):

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, इन के भाषण का ट्रांस्लेशन नहीं आ रहा है।

MR. SPEAKER: Today it is not possible to arrange for its translation.

Next time we will arrange for its translation. Mr. Patel, you may please finish your speech in two minutes.

*श्री उत्तम भाई पटेल (बलसार) : अध्यक्ष महोदय, यह जो 45वां संविधान संशोधन विधेयक पेश हुआ है, मैं उसका हार्दिक स्वागत करता हूं। करोड़ों आदिवासियों और हरिजनों में इस आरक्षण अवधि के समाप्त होने पर निराशा के बादल छाये हुए थे, लेकिन इस नई सरकार ने सत्ता में आते ही यह महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक पेश करके निराशा के बादल हटाने का जो कार्य किया है, उसके लिए मैं इस देश की प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी को धन्यवाद देता हूं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आज भी इस देश के कई नागरिक अपने मूल अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जो हम सब के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आर्थिक, शैक्षणिक और राजकीय दृष्टि से हरिजन और आदिवासी काफी पिछड़े हुए हैं।

आज भी गुजरात में धरमपुर जैसे जंगली क्षेत्र में आदिवासियों को पहनने के लिए केवल लंगोटी ही मिलती है।

बम्बई में आरे कालोनी में भैंसों को रखने के लिए जो सुविधा उपलब्ध है, उस से भी काफी बदतर हालत आदिवासियों और हरिजनों की है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस संशोधन विधेयक में आरक्षण के लिए जो व्यवस्था की गई है, उस पर पूरा-पूरा अमल करने के लिए तथा उसे युद्धस्तर पर प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को चेतावनी दिया जाना आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय, गुजरात राज्य की भांति आज भी अन्य राज्य भी हमारे देश में हैं, जहां नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए बाकायदा स्थान सुरक्षित रखे तो जाते हैं, लेकिन प्रथम और दूसरे वर्ग की नौकरियों में आरक्षित स्थानों पर नियुक्तियां ही नहीं की जातीं।

अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन विधेयक करोड़ों आदिवासियों और हरिजनों में नई चेतना पैदा करेगा।

अन्त में मैं अपनी ओर से एक नम्र निवेदन कर के अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा।

इस संशोधन विधेयक में आरक्षण की अवधि 10 वर्ष की ही रखी गई है। इस के बजाय, और अधिक–20 वर्ष की अवधि––बढ़ाने के लिए हमें सोचना जरूरी होगा।

अध्यक्ष महोदय : ज्ञानी जैल सिंह।

श्री सूरन भान (अम्बाला) : अध्यक्ष महोदय मुझे दो मिनट टाइम दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप का जितना टाइम था, उसका डबल-डबल टाइम मैंने दिया है। (व्यवधान) .....

आप दूसरी रीडिंग पर बोल लेना..... (व्यवधान)..... ऐसा कीजिए, आप दोनों दो–दो मिनट बोल लीजिए।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : माननीय अध्यक्ष जी, लोक सभा और विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों तथा जन–जातियों के लिए आरक्षण की अवधि बढाई जा रही है और इस सम्बन्ध में माननीय गृह मंत्री जी ने विधेयक पेश किया है। इस सम्बन्ध में आप ने मुझे जो टाइम दिया है, उस के लिये मैं आप का हृदय से आभारी हूं।

पेश्तर इस के कि मैं इस पर अपने विचार प्रकट करूं, मैं आप का ध्यान अनुसूचित जातियों एवं जन-जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण है, उस की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज़ादी के 32 साल बाद भी आज सरकारी नौकरियों में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का कोटा पूरा नहीं हुआ है। इसका एक मात्र कारण भारतीय संविधान का अनुच्छेद 335 है।

"335. The claims of the members of the Scheduled castes and the Scheduled Tribes shall be taken into consideration, consistently with the maintenance of efficiency of administration, in the making of appointments to services and posts in connection with the affairs of the Union or of a State".

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 335 ही सारी बुराइयों की जड़ है। अगर इस को डिलीट कर दिया जाए तो मेरा अपना विश्वास है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए जो नौकरियों में रिजर्वेशन है वह पूरा हो जाएगा क्योंकि "मेण्टीनन्स आफ़ एफीशियेन्सी आफ़ एडमिनिस्ट्रेशन" शब्द हमारे यहां के अच्छे–अच्छे काबिल, सुयोग्य और क्षमताशील लोगों को सर्विस में नहीं आने देते और इस वजह से उन को रिजेक्ट कर दिया जाता है कि आप काबिल नहीं हैं। इसलिए यह आर्टिकिल डिलीट होना चाहिए। अगर सर्विसेज में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का रिजर्वेशन पूरा नहीं होगा, तो राजनीतिक रिजर्वेशन का कोई माइने नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं है क्योंकि इस रिजर्वेशन ने जो राजनीतिक कार्यकर्त्ता पैदा किये हैं, देखने में यह आया है कि जितनी पालीटीकल पार्टीज हैं, उन में सवर्ण नेतृत्व है और वह नेतृत्व ही हावी है। जब भी

*The original speech was delivered in Gujarati.

[श्री चन्द्रपाल शैलानी]

टिकट देने का मसला आता है, तो सवर्ण हिन्दू नेतृत्व, इस बात पर जोर देता है कि जो हमारा बिस्तर ढोने वाले हैं, जीहजूरी करने वाले और पैर छूने वाले हैं, उनको ही टिकट मिलते हैं और जो योग्य हैं, जो पढ़े-लिखे हैं, जिन में राजनीतिक चेतना है, सूझबूझ है, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहते हैं, उन लोगों की उपेक्षा की जाती है। इस तरह से विधान सभाओं में और लोक सभा में जो रिजर्वेशन है उसके कारण ऐसे लोग यहां पर आ जाते हैं जो केवल हाथ उठाने का काम करते हैं।

15 hrs.

अध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : एक मिनट में खत्म कर रहा हूं। मैं आप का ध्यान कांस्टीचूयेन्ट एसेम्बली की प्रोसीडिंग्स की तरफ ले जाना चाहता हूं। बाबा साहब डा० अम्बेदकर ने जब शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए पोलीटीकल रिजर्वेशन की बात की थी और उस के लिए उन्होंने एक बिल पेश किया था, तो उस वक्त सर्वण जाति के हिन्दू नेतृत्व ने उस का विरोध किया था और यह कहा था कि 10 साल तो ज्यादा होते हैं, इस को पांच साल रखा जाए। मेरे जैसा इन्सान हैरान है, परेशान है कि दस-दस साल कर के इस को बढ़ाया जा रहा है। पहले 10, 10 साल करके 30 साल बढ़ाया और अब फिर 10 साल के लिए इस को बढा रहे हैं। इस में इन की क्या मंशा है, इन की क्या इन्टेंशन है, इन की क्या नीति है, यह मेरी समझ से बाहर है क्योंकि हमने यह देखा कि 30 साल के रिजर्वेशन के बाद भी जब श्री जगजीवन राम जी डा० सम्पूर्णानन्द की मूर्ति का अनावरण करने गये, तो उस के बाद उस को गंगा जल से धुलवाया गया। ..... (**व्यवधान**).... मैं केवल यह कहना चाहता हूं, मेरी मुख्य बात रह गई है, कि मैं इस बिल का विरोध नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे विरोध करने से कुछ होगा नहीं। जरूरत इस बात की है कि अगर सरकार यह चाहती है कि रिजर्वेशन बढ़ाया जाए, तो इस सम्मानित सदन में मैं एक सुझाव सरकार को देना चाहता हूं और मेरा सुझाव यह है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के लिए एक सेपरेट एलेक्टोरेट होना चाहिए, प्रथक निर्वाचन प्रणाली होनी चाहिए और उन का एक प्रथक निर्वाचक मंडल होना चाहिए, जिस से सही प्रतिनिधित्व उन का हो सके। अगर ऐसा किया जाएगा तो इस से इन लोगों का भला होगा।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि इन का प्रोपोर्शनल रेप्रेजेन्टेशन होना चाहिए। जिस तरह से राज्य सभा में और विधान परिषदों में चुनाव होता है और रेप्रेजेन्टेशन होता है, उसी तरह से इन के लिए भी होना चाहिए।.....(**व्यवधान**)....तादाद के बल पर आप मेरी आवाज को दबाना चाहते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप यह चाहते हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का सही रेप्रजेन्टेशन हाउस में हो तो उन का प्रोपोर्शनल रेप्रजेन्टेशन होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं आप को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : अध्यक्ष महोदय मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे बोलने का समय दिया। मैं इस बिल का स्वागत करता हूं लेकिन स्वागत करने के साथ-साथ इस बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस बिल के लाने के लिए ये इनडाइरेक्टली इस बात को एडमिट करते हैं कि पिछले 32, 33 सालों में इन लोगों की हालत में कोई ज्यादा सुधार नहीं हुआ, चाहे हुकूमत कोई भी रही हो। मुझे इस सम्बन्ध में एक शेर याद आ रहा है :

"हर चारागर को चारागरी से गुरेज था
वरना हमारा मर्ज कोई लादवा न था"।

अध्यक्ष महोदय मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि 10 साल के बाद फिर यह बिल लाना न पड़े, उस के लिए कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

सब से पहली बात तो यह है कि इन की हालत सुधारने के लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री हरिजनों व आदिवासियों के लिए अलग से बने जो कि इन के सारे कामों को देखे।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि इन की आबादी 20 फ़ीसदी है, इसलिए बजट का 20 फ़ीसदी रुपया इन के लिए रिजर्व किया जाए और वह इन लोगों की भलाई के कामों में खर्च किया जाए क्योंकि जब तक इन की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी ये अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते हैं।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सर्विसिज में जो रिजर्वेशन है, वह इम्प्लीमेंट नहीं की जा रही है। जो लोग इसे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, उनके लिए कानून में कोई सजा नहीं है। इस लिए मेरा सुझाव है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कानून पास किया जाए और उसमें प्राविजन किया जाए कि जो इसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उनको सजा मिलेगी। कई असेम्बलीज ने ऐसा कानून पास किया है। वेस्ट बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा सरकारें जब ऐसा कानून पास कर सकती हैं तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट क्यों नही पास कर सकती है? इसलिए इस तरह का कानून पास किया जाए।

चौथा सुझाव यह है कि इस बिल की रेटिफिकेशन स्टेट्स से होनी चाहिए और अगले सेशन से पहले होनी चाहिए। यह बेहतर होगा। इस बात की बड़ी चर्चा है, कहीं किसी गलतफहमी के कारण ऐसा न हो कि इस बिल को हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में ले जा कर रिजेक्ट करवा दिया जाए। मेहरबानी करके यह जरूर कीजिए।

अध्यक्ष महोदय दो काम और रह गये हैं। एक तो सिविल राइट्स प्रोटेक्शन की इम्प्लीमेन्टेशन का और दूसरा पिछली सरकार ने जो शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का कमीशन बनाया था उसको कांस्टीच्युशनल स्टेट्स देने का। इस कमीशन को कांस्टीच्यशनल स्टेटस दे दीजिए यह भी मेरा सुझाव है।

आखिर में, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार ने भी 1968 में रिविजन आफ दि लिस्ट आफ शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए एक कमेटी बिठाई थी और जनता सरकार ने भी बनाई थी जो कि पार्लियामेंट के टूटने के कारण रिवाइज नहीं हो पाई है। एक करोड़ ऐसे हरिजन हैं जो लिस्ट में नहीं हैं। वे लोग भी शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में शामिल हो जाएं ऐसा इन्तजाम और कर दीजिए।

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : माननीय सभापति महोदय इस बिल को पेश करते समय, मुझे खुशी है कि अपोजिशन की तरफ से यह सुझाव आया कि इस बिल को बगैर डिस्कशन के पास कर देना चाहिए। मैं इस बात के लिए भी मशकूर हूं कि ज्यादातर मेम्बर साहिबान ने सरकार को इस बिल के लिए बधाई दी है और इस बिल को खुशी से वेलकम किया है। जहां मेम्बर साहिबान ने इसे वेलकम किया, वहां कुछ सुझाव भी दिये जिनमें से कुछ सुझाव बहुत कीमती सुझाव हैं। जो डिबेट की कापी होगी उसे मैं अपनी टेबिल पर रखूंगा और देखूंगा कि कहां तक इस में कमी रह गई है जिससे कि उसे दूर कर सकूं और मेम्बर साहिबान के जो विचार हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करूं।

इस बिल पर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है मगर दो तीन बातें जो मेम्बर साहिबान की तरफ से कही गई हैं उनका जवाब देना बहुत जरूरी मालूम होता है। जहां इस बिल को दोस्तों ने वेलकम किया वहां दोस्तों ने यह भी कहा कि तीस साल तक जब हमारी सरकार शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कुछ नहीं कर सकी तो वह आइन्दा कैसे करेगी। यह भी कहा गया कि इसके लिए दस साल का वक्त बढ़ाने का मतलब यही एडमिट करना है कि इनके लिए अब तक कुछ नहीं किया गया। आखिर में, हमारे दोस्त ने एक शेर भी पढ़ा और बताया कि इस अर्से में भी कुछ होने वाला नहीं है इसका कोई फायदा उनको नहीं पहुंचेगा। उस तरफ की बेंचों पर बैठने वाले मेरे दोस्त जो ढाई साल तक इस तरफ बैठे रहे, आज उनकी बात को सुन कर आश्चर्य होता है। वे ढाई साल तक इधर की बेंचों पर बैठ कर मुल्क पर राज करते रहे और आज इस तरह की बातें कर रहे हैं।

मैं उन मेम्बर साहिबान से सहमत हूं जिन्होंने यह कहा कि उस दौरान हरिजनों को जिन्दा जलाया गया उनकी बहू-बेटियों की इस्मत लूटी गई, उनको उनके मकानों से निकाल दिया गया। (व्यवधान) मैं इस बात से भी सहमत हूं कि उस वक्त में स्वर्ण जाति के लोगों ने उनके साथ बहुत मजाक किया, उनकी रिजर्वेशन का मजाक उड़ाते हुए जुल्म जितना हो सकता था वह किया। लेकिन मैं आनरेबल मैम्बर्ज से अदब से कहना चाहता हूं कि आप गौर से देख लें।

फारश्तो उसको सब बता देना गुनाह मेरा
मगर इतना भी कह देना कि ये बातें सब---
जूवानी की थी।

जितना कुछ भी हुआ हरिजनों के साथ वह उस जमाने में हुआ जिस जमाने में हम लोग यहां नहीं थे। (इंटरप्शंज)।

SHRI EDUARDO FALEIRO (Mormugao) : Babu Jagjivan Ram has admitted that atrocities on Harijans have increased during the Janata Party rule.

श्री आर० एल० भाटिया (अमृतसर) : इससे आपके गुनाह नहीं छिपते।

श्री जैल सिंह : मैं आपकी मार्फत अपोजीशन ग्रुप्स के लीडर साहिबान से दरख्वास्त करूंगा कि वे अपने मैम्बरों पर कंट्रोल करें। अगर यही रास्ता अख्तयार किया गया तो हाउस की डिगनिटी में फर्क पड़ेगा और किसी के विचार जो हैं वे सामने नहीं आ सकेंगे।

मैं विरोधी दलों के मैम्बरों का बहुत सत्कार करता हूं और हमेशा से सत्कार करने वाला हूं। मैं डैमोक्रेसी में विश्वास रखता हूं। अभी एक मेम्बर ने, जो विरोधी दल के बैंचों पर बैठे हुए हैं, कहा कि मैं इस बिल का विरोध नहीं करता इसलिए कि मेरे विरोध करने से कुछ बनता नहीं है। इससे यह जाहिर होता है कि वह विरोध तो करना चाहते थे लेकिन उन्होंने जान लिया कि यह बिल तो पास हो ही जाएगा इसलिए इसका उन्हें विरोध नहीं करना चाहिए।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह शंका प्रकट की है कि इस रिजर्वेशन को खत्म कर देना चाहिए इस रिजर्वेशन से कुछ होता नहीं है। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि तीस साल के अर्से में स्वर्गवासी पंडित जवाहर लाल नेहरू ने और आज की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही इस सभा में आ कर इससे यह विधान बनवाया था। डा० अम्बेदकर इसके कर्ताधर्ता थे। उस जमाने में रिजर्वेशन का दस साल के लिए प्रावधान किया गया था और इस खयाल से हुआ था कि हम लोग तेजी के साथ इन लोगों को अपने साथ मिला सकें। दस साल के लिए इसको बढ़ाया गया। यह दस साल के लिए पंडित जी के जमाने में इसको बढ़ाया गया। और दस साल के लिए इंदिरा गांधी जी के जमाने

[श्री जैल सिंह]

में बढ़ाया गया। अब जो दस साल के लिए इसको बढ़ाया जा रहा है यह फिर श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में ही बढ़ाया जा रहा है। (इंटरप्शंज) मैं अपनी पार्टी के माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करता हूं कि वे बिल्कुल खामोश रहें कुछ न कहें। बड़े दिल और छोटे दिल का सबूत उस वक्त मिलता है जब आदमी मुसीबत में होता है या ताकत में होता है। आप ताकत में रह चुके हैं। अब अपोजीशन में बैठें तो बड़ा दिल बना कर बैठें। . . .

(व्यवधान)

श्री जैल सिंह : स्पीकर साहब, मैं आप को बताऊं हम को इस बात की खुशी है कि जब आप ट्रेजरी बैंचेज में रहे हम समझते थे कि वह एक डेमोक्रेसी की करामात थी। और अब भी डैमोक्रेसी की करामात है कि उन्होंने आप का इंतजार नहीं किया और 5 साल भी आप को नहीं दिये और उस तरफ बैठा दिया। .....

(*Interruptions*)

SRHI BAPUSAHEB PARULEKAR: On a point of order.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: He is on his legs. He wants to raise a point of order.

AN HON. MEMBER: Let him refer to the rule.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: I will quote the rule. I would request them not to assume the role of the Speaker. We have raised so many points during the debate on this Bill...

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Under what rule are you raising the point of order?

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: The hon. Minister is supposed to reply to the points raised in the debate.

MR. SPEAKER: There is no point of order. It is out of order.

श्री जैल सिंह : स्पीकर साहब, मैं बड़े दिल की बात करता हूं और विरोधी दल के नेताओं का सत्कार करता हूं। लेकिन जो बातें उन्होंने कहीं हैं उन का जिक्र न करूं तो यह अच्छा नहीं लगेगा। मैंने तो उन के शब्दो के मुताबिक ही कहा है। आप को बहुत बड़ा दिल दिखाना चाहिये। वहां बैठ कर हम ने भी बहुत सुनी है।

इस बिल का सब तरफ से स्वागत हुआ। मगर एक विरोधी दल के नेता ने कहा कि इस का कुछ फायदा नहीं है। मैं विरोध इस लिए नहीं करता क्योंकि मेरे विरोध करने से कुछ बनता नहीं। इस बात से उन को नाराज नहीं होना चाहिये। बल्कि सोचना चाहिये कि वे बहुत देर तक मैजोरिटी में और हुकूमत में रहे। लेकिन उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। फिर लोक दल की सरकार बनी और वह पार्लियामेंट में ही नहीं आई।

SHRI JYOTIRMOY BOSU: We are interested in the brilliant performance and we want him to be there.

श्री जैल सिंह : आनरेबल मैम्बर ने जो शब्द कहे हैं, मैं जानता हूं कि वह किस ख्याल से कहे हैं। उन्होंने परफार्मेन्स की बात कही है। मैं उन की परफार्मेन्स को भी अच्छी तरह से जानता हूं। यह भी मैं जानता हूं कि जब उन्होंने पायंट आफ आर्डर उठाना होता है, तो वह डिसआर्डर पैदा करने के लिये उठाते हैं।

लफ्जों की जगलरी से कुछ नहीं बनता है। हम एक सही बिल पास कर रहे हैं, जिस को यहां पर सब लोगों ने वैलकम किया है। मैं कुछ लोगों के संदेह को दूर करने के लिए ये बातें कह रहा हूं। मेरे खयाल से यह कहना गलतफहमी है कि तीस सालों में कुछ नहीं हुआ है। बहुत कुछ हुआ है। भारत वर्ष में सेन्ट्रल गवर्नमेंट हो, प्रान्तीय सरकार हो या यूनियन टैरिटरी की सरकार हो, रिजर्वेशन की वजह से कोई भी सरकार नहीं बन सकती है, अगर वहां पर हाउस में हरिजनों और आदिम जातियों को शामिल नहीं किया जाता है। लोक सभा में शेड्यूल्ड कास्ट्स के 79 मेम्बर्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के 40 मैम्बर्स हैं, इसी तरह स्टेट असेम्बलीज में शिडयूल्ड कास्ट्स के 556 मेम्बर्ज और शिडयूल्ड ट्राइब्स के 303 मेम्बर्ज शामिल होते हैं, तभी ये हाउस मुकम्मल होते हैं, वर्ना नहीं। बहुत सी आर्थिक समस्यायें हैं, जिन के बारे में राजनैतिक सत्ता मिलने के कारण शैड्यल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की सहायता हुई है। मगर यह काम बहुत ज्यादा है। हम इस को पूरा करने की कोशिश करते रहे हैं और करना चाहते हैं।

कुछ मेम्बर्ज साहबान ने जिक्र किया है कि हरिजनों से जमीनें छीनी गई। किस वक्त छीनी गई? मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जब 20 प्वाइंट प्रोग्राम लागू हुआ, तो हिन्दुस्तान के उन तमाम खेत मजदूरों को एग्रीकल्चरल लेबर को, जिन के पास घर नहीं था, मकान बनाने के लिए चार-चार मरले का प्लाट अलाट किया गया। इस के अलावा बांडिड लेबर को खत्म किया गया। सरकार इन बातों पर ध्यान दे रही थी, लेकिन बीच में कुछ विघ्न पड़ा और उस की वजह से आज फिर हम को दस साल का वक्त और बढ़ाना पड़ा है, ताकि हम इन जातियों के सम्मान, इज्जत, आर्थिक दशा और राजनैतिक दशा के मामले में दूसरों के बराबर ले आयें।

कुछ दोस्तों का यह ख्याल है कि दस साल और बढ़ाने से कुछ नहीं बनेगा, फिर दस साल बढ़ाना पड़ेगा। इस बात में काफी वजन है। हमने इस बात को देखना है। लेकिन अगर आज ही हम इस बात की चिन्ता, फिक्र, करने लगेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इस लिए यह कोशिश करनी चाहिये कि सरकार दस

साल में यह काम करे, और अगर फिर जरूरत पड़ती हैं, तो इस मुद्दत को और बढाया जा सकता है । लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि हम इस प्राविजन को खत्म कर दें ।

एक मैम्बर साहब ने कहा हैं कि रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं है , इस को खत्म कर देना चाहिए । (व्यवधान) मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा हूं, क्योकि ए आई ए डी एम के, डी एम के और जनता पार्टी में बहुत से दोस्तो ने इस को वैलकम किया है । उन्होने इस का विरोध नहीं किया है । एक दोस्त ने विरोध किया था, इसलिए मुझे कुछ कहना पड़ा है ।

एक आनरेबल मैम्बर ने यह कहा था कि ऐंग्लो इंडियन को नामजदगी दी जाती है उस की अब जरूरत नहीं रही । जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ तब तो यह बात ठीक थी, अब ठीक नहीं है । लेकिन मैं इस के ऊपर भी यह कहना चाहता हूं कि ऐंग्लो इंडियन बहुत कम गिनती में हैं, उन की संख्या बहुत थोड़ी है और वह भी हमारी सोसाइटी के अंग हैं । हमारी भारत सरकार की नीति और हमारे नेता की नीति यह है कि हिन्दुस्तान में किसी भी आंख में आंसू नहीं आना चाहिए और कोई भी यह महसूस न करे कि उस का ख्याल नहीं रखा गया है ।

मैम्बरों ने यह बात बिल्कुल दुरूस्त कही है कि बिलो पावर्टी ला।इन जो लोग हैं उन में ज्यादातर हरिजन और आदिवासी आते हैं । इसलिए भी यह जरूरी है कि यह पोलिटिकल रिजर्वेशन हो ताकि वह सर्विसेज में भी रिजर्वेशन ले सकें और वह इस बात का ध्यान रखें कि आर्थिक दृष्टि से जो काम सरकार करती है उस का फायदा सिर्फ अर्बन क्लास को ही नहीं होता हैं बल्कि इन को भी होता है । जो लोग यह कहते हैं कि रिजर्वेशन से कुछ फायदा नहीं हुआ उन से मैं कहना चाहता हूं कि उत्तम जाति के कमलापति जी जहां बैठते हैं, वहां पर बाबू जगजीवन राम जी उन से आगे बैठते थे । यह पंडित जवाहर लाल नेहरू जी की देन है और इस को इम्प्लीमेंट करने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी है ।

मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चहता । मैं मैम्बर साहबान का फिर शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्हो ने बहुत वैल्युएबल सजेशंज दिए हैं, अपनी राय दी है और इस बिल को वैलकम किया है ।

MR SPEAKER : Before I put the motion for consideration to the vote of the House, this being a Constitutional Amendment Bill, voting has to be by division. As Division Numbers have not so far been allotted to Members, it is not possible to hold the Division by Automatic Vote Recording Machine. Division will now take place by slip system. Members will be supplied at their seats with 'Aye'/'No' printed slips for recording their votes. 'Aye' slip is printed on one side in green, both in English and Hindi and 'No' in red on its reverse. On these slips, Members may kindly record votes of their choice by signing and writing their names, constituency and State/Union Territory and date legibly at the places specified on the slip. Members who desire to record 'Abstention' may ask for the 'Abstention' slip which is in yellow colour. Immediately after recording his vote, each Member should pass on his slip to the Division Clerk who will call upon his seat to collect the same for handing over to the Officers at the Table.

Now, let the lobbies be cleared.

The lobbies have been cleared.

MR. SPEAKER : The question is :

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

The Lok Sabha divided:

Division No. 1] **15.27 hrs.**

AYES

Abbasi, Shri Kazi Jalil
Abdul Samad, Shri
Acharia, Shri Basudeb
Agarwal, Shri Satish
Ahmed, Shri Mohd. Asrar
Ahmad, Shri Md. Kamaluddin
Ajit Pratap Singh, Shri
Alluri, Shri Subhash Chandra Bose
Amarender Singh, Shri
Anand Singh *alias* Annubhaiya, Shri
Anbarasu, Shri Era
Ansari, Shri Shafiqullah
Ansari, Shri Z. R.
Anthony, Shri Frank
Anuragi, Shri Godil Prasad
Anwar Ahmed, Shri
Appalanaidu, Shri S. R. A. S.
Arakal, Shri Xavier
Arjunan, Shri K.
Arunachalam, Shri M.
Ashfaq Hussain, Shri

Athare, Shri Chandrabhan Balaji
Azad, Shri Bhagwat Jha
Azad, Shri Gulam Nabi
Aziz Imam, Shri
Azmi, Shri A. U.

Bagun, Sumbrui, Shri
Baitha, Shri D. L.
Bajpai, Dr. Rajendra Kumari
Balan, Shri A. K.
Balanandan, Shri
Baleshwar Ram, Shri
Banatwala Shri G. M.
Bansi Lal, Shri
Banwari Lal, Shri
Barman, Shri Palas
Barot, Shri Maganbhai
Barrow, Shri A. E. T.
Barve, Shri J. C.
Basu, Shri Chitta
Behara, Shri Rasa Behari
Bhagat, Shri Baliram
Bhagat, Shri H. K. L.
Bhagwan Dev, Shri
Bhakta, Shri Manoranjan
Bhardwaj, Shri Parasram
Bhatia, Shri R. L.
Bhattacharya, Shri Sushil Kumar
Bhikhabhai, Shri
Bhoi, Dr. Karupa Sindhu
Bhole, Shri R. R.
Bhoye Reshma Motiram, Shri
Bhuria, Shri Dileep Singh
Bijendra Pal Singh, Shri
Birbal, Shri
Birender Singh Rao, Shri
Biswas, Shri Ajoy
Boddepalli, Shri Rajagopala Rao
Bosu, Shri Jyotirmoy
Buta Singh, Shri

Chakraborty, Shri Satyasadhan
Chakradhari, Shri
Chandra Pal Singh, Shri
Chandra Shekhar Singh, Shri
Chandrakar, Shri Chandulal
Chandrasekharappa, Shri T. V.
Charanjit Singh, Shri
Chatterjee, Shri Somnath
Chaturbhuj, Shri
Chaturvedi, Shrimati Vidyavati
Chaudhary, Shri R. Motibhai
Chaudhury, Shri Tridib
Chavan, Shri Shankarrao Bhaurao
Chavan, Shri Y. B.
Chavda, Shri Ishwarbhai Khodabhai
Chawdhury, Shri A. B. A. Ghani
Chennupati, Shrimati Vidya
Chingwang Konyak, Shri
Chiranji Lal Sharma, Shri
Chitturi Subba Rao Chowdhary, Shri
Choubey, Shri Narayan
Choudhari, Shrimati Usha Prakash
Chouhan, Shri Fatebhanu Singh
Chowdhary, Shri Saifuddin

Dabhi, Shri Ajitsinh
Daga, Shri Mool Chand
Dalbir Singh, Shri
Damor, Shri Somjibhai
Dandavate, Prof. Madhu
Dandavate, Shrimati Pramila
Das, Shri A. C.
Das, Shri R. P.
Dennis, Shri N.
Deo, Shri K. P. Singh
Deo, Shri V. Kishore Chandra S.
Desai, Shri B. V.
Devarajan, Shri B.
Devinder Singh, Shri
Dhandapani, Shri C. T.
Dharmgaj Singh, Shri
Digvijay Singh, Shri
Dogra, Shri G. L.
Doongar Singh, Shri
Dorai Sebastian, Shri S. A.
Dubey, Shri Bindeshwari
Dubey, Shri Ram Nath

Ekka, Shri Christopher
Era Mihan *alias* Ram Mohan R., Shri
Faleiro, Shri Eduardo
Fernandes, Shri George
Fernandes, Shri Oscar
Gadgil, Shri V. N.
Gadhavi, Shri Bheravadan K.
Gaekwad, Shri R. P.
Gaikwad, Shri Udaysingrao
Gamit, Shri Chhitubhai
Gandhi, Shrimati Indira
Gandhi, Shri Sanjay
Gehlot, Shri Ashok
Ghorpade, Shri R. Y.
Ghosh, Shri Niren
Giri, Shri Sudhir Kumar
Giriraj Singh, Shri
Goel, Shri K. K.
Gohil, Shri G. B.
Gomango, Shri Giridhar
Gopalan, Shrimati Suseela
Goswami, Shrimati Bibha Ghosh
Gounder, Shri A. Senapathi
Gouzagin, Shri
Gowda, Shri D. M. Putte
Gufran Azam, Shri
Gulsher Ahmed, Shri
Gupta, Shri Indrajit
Gurbinder Kaur, Shrimati
Gurcharan Singh, Shri
Hakam Singh, Shri
Halder, Shri Krishna Chandra
Hannan Mollah, Shri
Harikesh Bahadur, Shri
Hasda, Shri Matilal
Horo, Shri N. E.
Imbichi Bava, Shri E. K.
Indra Kumari, Shrimati
Jaffer Sharief, Shri C. K.
Jagjivan Ram, Shri
Jagpal Singh, Shri
Jai Narayan, Shri
Jaiba, Smt. Rane Sirdessai Saynogita
Jain, Shri Bhiku Ram
Jain, Shri Virdhi Chand
Jaydeep Singh, Shri
Jena, Shri Chintamani
Jethmalani, Shri Ram
Jha, Shri Kamal Nath
Jharkhande Rai, Shri
Jitendra Prasad, Shri
Kailash Pati, Shrimati
Kalanidhi, Shri A.
Kalpnath Shankar, Shri
Kamakshaiah, Shri D.
Kamal Nath, Shri
Kamla Kumari, Shrimati
Kandaswamy, Shri M.
Karan Singh, Dr.
Karma, Shri Lachman
Karunanithi Thazhai, Shri
Kashirsagar, Shrimati Kesharbai
Kashyap, Shri Jaipal Singh
Kaul, Shrimati Sheila
Kaushal, Shri Jagannath
Keyur Bhusan, Shri
Khan, Shri Arif Mohammad
Khan, Shri Gayoor Ali
Khan, Shri Malik M. M. A.
Khan, Shri Zulfiquar Ali
Kidwai, Shrimati Mohsina
Kochack, Shri Ch. Rasool
Kodiyan, Shri P. K. Adoor
Krishan Pratap Singh, Shri
Kuchan, Shri Gangadhar S.
Kulandaivelu, Shri V.
Kunhambu, Shri K.
Kunwar Ram, Shri
Lakkappa, Shri K.
Lakshmanan, Shri G.
Laskar, Shri Nihar
Lawrence, Shri M. M.
Madhukar, Shri Kamla Mishra
Mahabir Prasad, Shri
Mahajan, Shri Vikram
Mahajan, Shri Y. S.
Mahala, Shri R. P.
Mahata, Shri C. R.

Mahendra Prasad, Shri
Maitra, Shri Sunil
Makwana, Shri Narsinh
Mallanna, Shri K.
Mallikarjun, Shri
Mallu, Shri A. R.
Mandal, Shri Sanat Kumar
Mani, Shri K. B. S.
Manphool Singh, Shri
Meena, Shri Ram Kumar
Mehta, Shri Ajit Kumar
Mehta, Dr. Mahipatray M.
Mhalgi, Shri R. K.
Mirdha, Shri Nathu Ram
Mishra, Shri Hari Nath
Mishra, Shri Ram Nagina
Mishra, Shri Satyagopal
Mohammed Ismail, Shri
Mohanty, Shri Brajamohan
Mohite, Shri Yashawantrao
More, Shri Ram Krishna
Motilal Singh, Shri
Mukherjee, Shrimati Geeta
Mukherjee, Shri Samar
Mukhopadhyaya, Shri Anand Gopal
Mundackal, Shri George Joseph
Murthy, Shri Kusuma Krishna
Murthy, Shri M. Rajashekara
Murthy, Shri M. V. Chandrashekhara
Murugian, Shri
Muttemwar, Shri Vilas
Nadar, Shri A. Neelalohithadasan
Nagaratnam, Shri T.
Nahata, Shri B. R.
Naidu, Shri P. Rajagopal
Naik, Shri Surupsing H.
Naikar, Shri D. K.
Nair, Shri B. K.
Nanje Gowda, Shri H. N.
Narayana, Shri K. S.
Naval Kishore Sharma, Shri
Nayak, Shri Mrutyunjaya
Negi, Shri T. S.
Netam, Shri Arvind
Ngangom Mohendra, Shri
Nihal Singh, Shri
Nikhra, Shri Rameshwar
Nitya Nanda, Shri
Pahadia, Shri Jagannath
Palaniappan, Shri C.
Pandey, Shri Kedar
Pandey, Shri Krishna Chandra
Panigrahi, Shri Chintamani
Panika, Shri Ram Pyare
Parashar, Prof. Narain Chand
Pardhi, Shri Keshaorao
Parmar, Shri Hiralal R.
Parthasarathy, Shri P.
Parulekar, Shri Bapusaheb
Paswan, Shri Ram Vilas
Patel, Shri Ahmed Mohammed
Patel, Shri Amrit
Patel, Shri C. D.
Patel, Shri Shantubhai
Patel, Shri U. H.
Pathak, Shri Anand
Patil, Shri Balasaheb Vikhe
Patil, Shri Shankarrao
Patil, Shri Shivraj V.
Patil, Shri A. T.
Patil, Shri Uttamrao
Patil, Shri Vasantrao
Patil, Shri Veerendra
Patil, Shri Vijay N.
Patnaik, Shri Janki Ballav
Pattuswamy, Shri D.
Penchalaiah, Shri
Phulwariya, Shri Virda Ram
Pilot, Shri Rajesh
Poojary, Shri Janardhana
Prabhu, Shri R.
Pradhan, Shri Amar Roy
Pradhani, Shri K.
Prasanna, Shri S. N.
Pullaiah, Shri Darur
Pushpa Devi Singh, Kumari
Qazi Saleem, Shri
Quadri, Shri S. T.

Raghavan, Shri V. S. Vijaya
Rahi, Shri Ram Lal
Rahim, Shri A. A.
Rajamallu, Shri K.
Rajan, Shri K. A.
Rajda, Shri Ratansinh
Rajesh Kumar Singh, Shri
Raju, Shri P. V. G.
Rakesh, Shri R. N.
Ram, Shri Ramswaroop
Ramalingam, Shri N.
Ramamurthy, Shri K.
Ramanna Rai, Shri M.
Ramayan Rai, Shri
Ramulu, Shri H. G.
Ranbir Singh, Shri
Ranga, Shri N. G.
Ranjit Singh, Shri
Rao, Shri Ankineedu Prasada
Rao, Shrimati B. Radhabai Ananda
Rao, Shri Jagannath
Rao, Shri Jalagam Kondala
Rao, Shri M. Nageswara
Rao, Shri M. S. Sanjeevi
Rao, Shri M. Satyanarayana
Rao, Shri S. B. P. Pattabhi Rama
Rasheed Masood, Shri
Rathawa, Shri Amar Sinh
Rathod, Shri Uttam
Raut, Shri Bhola
Ravani, Shri Navin
Rawat, Shri Harish
Reddy, Shri G. S.
Reddy, Shri G. Narsimha
Reddy, Shri K. Vijay Bhaskara
Reddy, Shri M. Ram Gopal
Reddy, Shri P. Venkata
Riyan, Shri Baju Ban
Rothuama, Dr. R.
Roy, Shri A. K.
Roy, Dr. Saradish
Saha, Shri Gadadhar
Sahi, Shrimati Krishna
Sahu, Shri Narayan
Sajjan Kumar, Shri
Samin Uddin, Shri
Sangama, Shri P. A.
Sathe, Shri Vasant
Satish Prasad Singh, Shri
Satya Deo Singh, Prof.
Sayeed, Shri P. M.
Sawant, Shri T. M.
Selvaraju, Shri N. B. E.
Sethi, Shri Arjun
Sethi, Shri P. C.
Shailani, Shri Chandra Pal
Shaktawat, Prof. Nirmala Kumari
Shakya, Shri Ram Singh
Shakyawar, Shri Nathuram
Shamanna, Shri T. R.
Shantaram, Shri
Sharma, Shri K. C.
Sharma, Shri Munder
Sharma, Shri Nand Kishore
Sharma, Shri Pratap Bhanu
Sharma, Dr. Shankar Dayal
Sharma, Shri Vishwa Nath
Shastri, Shri Dharam Dass
Shastri, Shri Harikishan
Shastri, Shri Ramavatar
Shingada, Shri D. B.
Shiv Shankar, Shri P.
Shivendra Bahadur Singh, Shri
Shivkumar Singh, Shri Thakur
Sidnal, Shri S. B.
Singaravadivel, Shri S.
Singh, Shri B. D.
Singh, Shri C. P. N.
Sinha, Shri Dharam Bir
Sinha, Shrimati Ramdulari
Sivaprakasam, Shri D. S. A.
Solanki, Shri Babu Lal
Solanki, Shri Natvarsinh
Sontosh Mohan Dev, Shri
Soundararajan, Shri N.
Sparrow, General R. S.
Sreenivasa Prasad, Shri V.
Subbe, Shri P. M.

Sukhadia, Shri Mohanlal
Sukhbuns Kaur, Shrimati
Sunder Singh, Shri
Suraj Bhan, Shri
Surya Narayan Singh, Shri
Suryawanshi, Shri Narsing Rao
Swami, Shri K. A.
Syed, Shri Masudal Hossain
Tapeshwar Singh, Shri
Tariq Anwar, Shri
Tayeng, Shri Sobeng
Tayyab Husain, Shri
Tewari, Shri Chandra Bhal Mani
Tewari, Shri Narayan Datt
Tewary, Prof. K. K.
Thorat, Shri Bhausaheb
Thummalapalli, Shri Damodhar Reddy
Thungon, Shri Prem Khandu
Tirkey, Shri Pius
Tripathi, Shri Kamalapati
Tudu, Shri Manmohan
Tytler, Shri Jagdish
Uike, Shri Chhotelal
Vairale, Shri Madhusudan
Venkataraman, Shri R.
Velu, Shri A. M.
Venkatasubbaiah, Shri P.
Verma, Shri Chandradeo Prasad
Verma, Shri Jai Ram
Verma, Shri R. L. P.
Verma, Shri Raghunath Singh
Vishwa Nath Pratap Singh, Shri
Vyas, Shri Girdhari Lal
Wagh, Dr. Pratap
Wasnik, Shri Balkrishna Ramchandra
Yadav, Shri Chandrajit
Yadav, Shri D. P.
Yadav, Shri Ram Singh
Yadav, Shri Subhash Chandra
Yadav, Shri Vijay Kumar
Yazdani, Shri Golam
Yellaiah, Shri Nandi
Yusuf, Shri M.
Zail Singh, Shri
Zainal Abedin, Shri
Zainul Basher, Shri

NOES

Nil

MR. SPEAKER: The result of the division is: Ayes 416; Noes nil. The 'Ayes' have it, the 'Ayes' have it. The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting.

The motion was adopted.

Clause 2— (*Amendment of article 334.*)

MR. SPEAKER: We now take up Clause 2. There are some amendments.

SHRI RAM VILAS PASWAN: I beg to move:

Page 1, line 8,—

for "forty years" substitute—
"sixty years". (1)

MR. SPEAKER: Shri Ram Lal Rahi. Is he moving his amendment?

SHRI RAM LAL RAHI: I am not moving.

MR. SPEAKER: Shri Mool Chand Daga. Is he moving his amendment?

SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali): Not moving. I want to speak for a minute.

श्री राम विलास पासवान : अभी दोनों ओर के माननीय सदस्यों ने जोर जोर से कहा कि हरिजनों का रिजर्वेशन होना चाहिए। यह भी कहा कि हरिजनों के हित के जितने काम होने चाहियें नहीं हो सके। आप चाहे सरकारी नौकरियों के आंकड़ों को देख लें या हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों को देख लें इनमें कमी नहीं आ रही है वे बढ़ रहे हैं और नौकरियों में भी इन के अधिकार इन को नहीं मिल सके हैं। तमाम सुझाव दिए जा रहे हैं। इन को जीव जन्तु ही समझा जाता है। चारों शंकराचार्य पुरी में बैठे हुए हैं। वहां से वे फरमान जारी करते हैं कि अछूत पेट से ही अछूत के रूप में पैदा हुआ है और उस पर अमल होता है। श्री जगजीवन राम से बढ़ कर कोई हरिजनों का बड़ा नेता नहीं हो सकता है। उनके हाथों डा० सम्पूर्णा नन्द की मूर्ति का जब अनावरण किया जाता है तो उस मूर्ति को फिरसे धोया जाता है और यह काम उन लोगों के द्वारा किया गया था जो उधर बैठे हुए हैं। (इंटरप्शंज)

एक माननीय सदस्य : आप के राज्य में यह सब हुआ था।

श्री राम विलास पासवान : हम लोग चाहे जनता पार्टी में थे या लोक दल में आप प्रोसीडिंग्ज उठा कर देख लें, जब कभी हरिजनों, अनुसूचित जातियों या जन-जातियों का मामला आया, साठे साहब तथा दूसरे मित्र जानते हैं कि हम लोगों ने एक स्वर से उस का समर्थन किया था, हम लोगों ने किसी से कम आवाज नहीं उठाई थी। इस बात का हमें गर्व है। हम चाहते हैं कि हरिजन, आदिवासी जन जाति आदि के जितने भी माननीय सदस्य हैं वे चाहे किसी भी ओर बैठें हों, सभी इन जातियों के हितों की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध हों। हम को बांडिड लेबर, बंधवा मजदूर नहीं बनाना चाहिये मैंने जो संशोधन दिया है मैं चाहता हूं कि विरोधी दल के तथा सत्ताधारी दल के माननीय सदस्य उसका एक स्वर से समर्थन करें। मैंने अपने संशोधन में कहा है कि सरकार जो दस साल के लिए इस रिजर्वेशन को बढ़ा रही है इसको बढ़ाकर के आप को तीस साल कर देना चाहिये। यह संशोधन मैंने इसलिए दिया है ताकि कहीं कल को आपकी ईटेंशन, आप का मोटिव गलत न हो जाए, आपकी नीयत गलत न हो जाए। मैं चाहता हूं कि सारा सदन एक स्वर से इसको पास करे।

श्री जैल सिंह : आनरेबल मैम्बर के सुझाव को मैंने बड़े ग़ौर से देखा है। लेकिन इस को मैं मंजूर नहीं कर सकता क्योंकि इसको मंजूर करने से ढिलाई पैदा हो जाएगी। काम में सुस्ती रहेगी। हम को दस साल इसलिए रखना है कि हम उन को दस साल के अन्दर अपने बराबर लाना चाहते है दूसरी जातियों के बराबर लाना चाहते है। अगर वे नही आते है, तो और समय भी दिया जा सकता है कोई इस में बाधा नहीं है। इस अवधि को बांधा नहीं जा सकता है। लेकिन आज हम को सिर्फ दस साल ही इस अवधि को बढ़ाना चाहिये।

MR. SPEAKER: So, do you persist with it?

SHRI RAM VILAS PASWAN: Yes.

MR. SPEAKER: I shall now put Amendment No. 1 to Clause 2 moved by Shri Ram Vilas Paswan to the vote of the House.

Amendment No. 1 was put and negatived.

MR. SPEAKER: Now, Clause 2 has to be put to the vote. If the House agrees, I shall now put Clauses 1 and 2 together to the vote of the House because there is no amendment to Clause 1.

Before I put Clauses 1 and 2 to the vote of the House, this being a Constitution Amendment Bill, voting has to be taken by division. Let the lobbies be cleared....

Now the lobbies have been cleared.

The question is:

"That Clauses 2 and 1 stand part of the Bill."

The Lok Sabha divided:

Division No. 2] .. .. **[16 hrs.**

AYES

Abbasi, Shri Kazi Jalil
Abdul Samad, Shri
Acharia, Shri Basudeb
Agarwal, Shri Satish
Ahmed, Shri Mohd. Asrar
Ahmad, Shri Md. Kamaluddin
Ajit Pratap Singh, Shri
Alluri, Shri Subhash Chandra Bose
Amarender Singh, Shri
Anand Singh, alas Annubhaiya, Shri
Anbarasu, Shri Era
Ansari, Shri Shafiqu-llah
Ansari, Shri Z. R.
Anthony, Shri Frank
Anuragi, Shri Godil Prasad
Anwar Ahmed, Shri
Appalanaidu, Shri S.R.A.S.

Arakal, Shri Xavier
Arjunan, Shri K.
Arunachalam, Shri M.
Ashfaq Hussain, Shri
Athare, Shri Chandrabhan Balaji
Azad, Shri Bhagwat Jha
Azad, Shri Gulam Nabi
Aziz Imam, Shri
Bagun Sumbru, Shri
Baitha, Shri D. L.
Bajpai, Dr. Rajendra Kumari
Balan, Shri A. K.
Balanandan, Shri
Baleshwar Ram, Shri
Banatwalla, Shri G. M.
Bansi Lal, Shri
Banwari Lal, Shri
Barman, Shri Palas
Barot, Shri Maganbhai
Barrow, Shri A. E. T.
Barve, Shri J. C.
Basu, Shri Chitta
Behara, Shri Rasa Behari
Bhagat, Singh Baliram
Bhagat, Shri H. K. L.
Bhagwan Dev, Shri
Bhakta, Shri Manoranjan
Bhardwaj, Shri Parasram
Bhatia, Shri R. L.
Bhattacharya, Shri Sushil Kumar
Bhikhabhai, Shri
Bhim Singh, Shri
Bhoi, Dr. Krupa Sindhu
Bhole, Shri R. R.
Bhoye Reshma Motiram, Shri
Bhuria, Shri Dileep Singh
Bijendra Pal Singh, Shri
Birbal, Shri
Birendra Singh Rao, Shri
Biswas, Shri Ajoy
Boddepalli, Shri Rajagopala Rao
Bosu, Shri Jyotirmoy
Buta Singh, Shri
Chakraborty, Shri Satyasadhan
Chakradhari, Shri
Chandra Pal Singh, Shri
Chandra Shekhar Singh, Shri
Chandrakar, Shri Chandulal
Chandrasekharappa, Shri T. V.
Charanjit Singh, Shri
Chatterjee, Shri Somnath
Chaturbhuj, Shri
Chaturvedi, Shrimati Vidyavati
Chaudhary, Shri R. Motibhai
Chaudhury, Shri Tridib
Chavan, Shri Shankarrao Bhaurao
Chavan, Shri Y. B.
Chavda, Shri Ishwarbhai Khodabhai
Chawdhury, A. B. A. Ghani
Chennupati, Shrimati Vidya
Chingwang Konyak, Shri
Chitturi, Shri Subba Rao Chowdhary
Choubey, Shri Narayan
Choudhari, Shri K. B.
Choudhari Shrimati Usha Prakash
Chouhan, Shri Fatebhanu Singh
Chowdhary, Shri Saifuddin
Dabhi, Shri Ajitsingh
Daga, Shri Mool Chand
Dalbir Singh, Shri
Damor, Shri Somjibhai
Dandavate, Prof. Madhu
Dandavate, Shrimati Pramila
Das, Shri A. C.
Das, Shri R. P.
Dennis, Shri N.
Deo, Shri K. P. Singh
Deo, Shri V. Kishore Chandra S.
Desai, Shri B. V.
Devarajan, Shri B.
Devinder Singh, Garcha, Shri
Dhandapani, Shri C. T.
Dharamgaj Singh, Shri
Digvijay Singh, Shri
Dogra, Shri G. L.
Doongar Singh, Shri

Dorai Sebastian, Shri S. A.
Dubey, Shri Bindeshwari
Dubey, Shri Ram nath
Ekka, Shri Christopher
Era Mohan alias Ram Mohan R., Shri
Faleiro, Shri Eduardo
Fernandes, Shri George
Fernandes, Shri Oscar
Gadgil, Shri V. N.
Gadavi, Shri Bheravadan K.
Gaekwad, Shri R. P.
Gaikwad, Shri Udaysingrao
Gamit, Shri Chhitubhai
Gandhi, Shrimati Indira
Gandhi; Shri Sanjay
Gehlot, Shri Ashok
Ghorpade, Shri R. Y.
Ghosh, Shri Niren
Giri, Shri Sudhir Kumar
Giriraj Singh, Shri
Goel, Shri K. K.
Gohil, Shri G. B.
Gomango, Shri Giridhar
Gopalan, Shrimati Suseela
Goswami, Shrimati Bibha Ghosh
Gounder, Shri A. Senapathi
Gouzagin, Shri
Gowda, Shri D. M. Putte
Gufran Azam, Shri
Gulsher Ahmed, Shri
Gupta, Shri Indrajit
Gurbinder Kaur, Shrimati
Gurcharan Singh, Shri
Hakam Singh, Shri
Halder, Shri Krishna Chandra
Hannan Mollah, Shri
Harikesh Bahadur, Shri
Hasda, Shri Matilal
Horo, Shri N. E.
Imbichi Bava, Shri E. K.
Jaffer Sharief, Shri C. K.
Jagjivan Ram, Shri
Jagpal Singh, Shri
Jai Narayan, Shri
Jaiba, Smt. Rane Sirdessai Saynogita
Jain, Shri Bhiku Ram
Jain, Shri Virdhi Chand
Jaydeep Singh, Shri
Jena, Shri Chintamani
Jethmalani, Shri Ram
Jha, Shri Kamal Nath
Jharkhande, Rai, Shri
Jitendra Prasad, Shri
Kailash Pati, Shrimati
Kalanidhi, Shri A.
Kalpnath Shankar, Shri
Kamakshaiah, Shri D.
Kamal Nath, Shri
Kamla Kumari, Shrimati
Kandaswamy, Shri M.
Karan Singh, Dr.
Karma, Shri Lachman
Karunanithi Thazhai, Shri
Kashirsagar, Shrimati Kesharbai
Kashyap, Shri Jaipal Singh
Kaul, Shrimati Sheila
Kaushal, Shri Jagannath
Keyur Bhusan, Shri
Khan, Shri Arif Mohammad
Khan, Shri Ghayoor Ali
Khan, Shri Malik M. M. A.
Khan, Shri Zulfikuar Ali
Kidwai, Shrimati Mohsina
Kochack, Shri Ghulam Rasool
Kodiyan, Shri P. K.
Krishan Pratap Singh, Shri
Krishnan, Shri G. Y.
Kuchan, Shri Gangadhar S.
Kulandaivelu, Shri V.
Kunhambu, Shri K.
Kunwar Ram, Shri
Lakkappa, Shri K.
Lakshmanan, Shri G.
Laskar, Shri Nihar
Lawrence, Shri M. M.

Madhukar, Shri Kamla Mishra
Mahabir Prasad, Shri
Mahajan, Shri Vikram
Mahajan, Shri Y. S.
Mahala, Shri R. P.
Mahata, Shri C. R.
Mahendra Prasad, Shri
Maitra, Shri Sunil
Makwana, Shri Narsinh
Mallanna, Shri K.
Mallikarjun, Shri
Mallu, Shri A. R.
Mandal, Shri Sanat Kumar
Mani, Shri K. B. S.
Manphool Singh, Shri
Meena, Shri Ram Kumar
Mehta, Shri Ajit Kumar
Mehta, Dr. Mahipatray M.
Mhalgi, Shri R. K.
Mirdha, Shri Nathu Ram
Mishra, Shri Hari Nath
Mishra, Shri Ram Nagina
Mishra, Shri Satyagopal
Mohammed Ismail, Shri
Mohanty, Shri Brajamohan
Mohite, Shri Yashwantrao
More, Shri Ram Krishna
Motilal Singh, Shri
Mukherjee, Shrimati Geeta
Mukherjee, Shri Samar
Mukhopadhyaya, Shri Anand Gopal
Mundackal Shri George Joseph
Murthy, Shri Kusuma Krishna
Murthy, Shri M. Rajashekara
Murthy, Shri M. V. Chandrasekhara
Murugian, Shri
Muttemwar, Shri Vilas
Nadar, Shri A. Neelalohithadasan
Nagaratnam, Shri T.
Nahata, Shri B. R.
Naidu, Shri P. Rajagopal
Naik, Shri Surup Singh, H.
Naikar, Shri D. K.
Nair, Shri B. K.
Nanje Gowda, Shri H. N.
Narayana, Shri K. S.
Naval Kishore Sharma, Shri
Nayak, Shri Mrutyanjaya
Negi, Shri T. S.
Netam, Shri Arvind
Ngangom Mohendra, Shri
Nihal Singh, Shri
Nikhra, Shri Rameshwar
Nitya Nanda Misra, Shri
Odedra, Shri Maldevji M.
Oraon, Shri Kartik
Pahadia, Shri Jagannath
Palaniappan, Shri C.
Pandey, Shri Kedar
Pandey, Shri Krishna Chandra
Panigrahi, Shri Chintamani
Panika, Shri Ram Pyare
Parashar, Prof. Narain Chand
Paradhi, Shri Keshaorao
Parmar, Shri Hiralal R.
Parthasarthy, Shri P.
Parulekar, Shri Bapusaheb
Paswan, Shri Ram Vilas
Patel, Shri Ahmed Mohammed
Patel, Shri Amrit
Patel, Shri C. D.
Patel, Shri Shantubhai
Patel, Shri U. H.
Pathak, Shri Anand
Patil, Shri Balasaheb Vikhe
Patil, Shri Shankarrao
Patil, Shri Shivraj V.
Patil, Shri A. T.
Patil, Shri Uttamrao
Patil, Shri Vasantrao
Patil, Shri Veerendra
Patil, Shri Vijay N.
Patnaik, Shri Janki Ballav
Pattuswamy, Shri D.
Penchalaiah, Shri
Phulwariya, Shri Virda Ram

Pilot, Shri Rajesh
Poojary, Shri Janardhana
Prabhu, Shri R.
Pradhan, Shri Amar Roy
Pradhani, Shri K.
Prasanna, Shri S. N.
Pullaiah, Shri Darur
Pushpa Devi Singh, Kumari
Qazi Saleen, Shri
Quadri, Shri S. T.
Raghavan, Shri V. S. Vijaya
Rahi, Shri Ram Lal
Rahim, Shri A. A.
Rajamallu, Shri K.
Rajan, Shri K. A.
Rajda, Shri Ratansinh
Rajesh Kumar Singh, Shri
Raju, Shri P. V. G.
Rakesh, Shri R. N.
Ram, Shri Ramswaroop
Ramalingam, Shri N. Kudanthai
Ramamurthy, Shri K.
Ramanna Rai, Shri M.
Ramayan Rai, Shri
Ramulu, Shri H. G.
Ranabir Singh, Shri
Ranga, Shri N. G.
Ranjit Singh, Shri
Rao, Shri Ankineedu Prasada
Rao, Shrimati B. Radhabai Ananda
Rao, Shri Jagannath
Rao, Shri Jalagam Kondala
Rao, Shri M. Nageswara
Rao, Shri M. S. Sanjeevi
Rao, Shri M. Satyanarayana
Rao, Shri S. B. P. Pattabhi Rama
Rasheed Masood, Shri
Rathawa, Shri Amar Singh
Rathod, Shri Uttam
Raut, Shri Bhola
Ravani, Shri Navin
Rawat, Shri Harish
Reddy, Shri G. S.
Reddy, Shri G. Narsimha
Reddy, Shri K. Brahmananda
Reddy, Shri K. Vijay Bhaskara
Reddy, Shri M. Ram Gopal
Reddy, Shri P. Venkata
Riyan, Shri Baju Ban
Rothuama, Dr. R.
Roy, Shri A. K.
Roy, Dr. Saradish
Saha, Shri Gadadhar
Sahi, Shrimati Krishna
Sahu, Shri Narayan
Sajjan Kumar, Shri
Samin Uddin, Shri
Sangama, Shri P. A.
Sathe, Shri Vasant
Satish Prasad Singh, Shri
Sawant, Shri T. M.
Sayeed, Shri P. M.
Selvaraju, Shri N. B. E.
Sethi, Shri Arjun
Sethi, Shri Prakash Chand
Shailani, Shri Chandra Pal
Shaktawat, Prof. Nirmal Kumari
Shakya, Shri Ram Singh
Shakyawar, Shri Nathuram
Shamanna, Shri T. R.
Shankaranand, Shri B.
Shantaram, Shri
Sharma, Shri K. C.
Sharma, Shri Munder
Sharma, Shri Nand Kishore
Sharma, Shri Pratap Bhanu
Sharma, Dr. Shankar Dayal
Sharma, Shri Vishwa Nath
Shastri, Shri Dharam Dass
Shastri, Shri Harikishan
Shastri, Shri Ramavatar
Shingda, Shri D. B.
Shiv Shankar, Shri P.
Shivendra Bahadur Singh, Shri
Shivkumar Singh, Shri Thakur
Shukla, Shri Vidya Charan
Sidnal, Shri S. B.

Singaravadivel, Shri S.
Singh, Shri B. D.
Singh, Shri C. P. N.
Sinha, Shri Dharam Bir
Sinha, Shrimati Ramdulari
Sivaprakasam, Shri D. S. A.
Solanki, Shri Babu Lal
Solanki, Shri Natvarsinh
Sontosh Mohan Dev, Shri
Soundararajan, Shri N.
Sparrow, General R. S.
Sreenivasa Prasad, Shri V.
Subbe, Shri P. M.
Sukhadia, Shri Mohanlal
Sukhbuns Kaur, Shrimati
Sunder Singh, Shri
Suraj Bhan, Shri
Surya Narayan Singh, Shri
Suryawanshi, Shri Narsing Rao
Swami, Shri K. A.
Swamy, Dr. Subramaniam
Syed, Shri Masudal Hossain
Tapeshwar Singh, Shri
Tariq Anwar, Shri
Tayeng, Shri Sobeng
Tayyab Husain, Shri
Tewari, Shri Chandra Bhal Mani
Tewari, Shri Narayan Dutt
Tewary, Prof. K. K.
Thorat, Shri Bhausaheb
Thummalapalli. Shri Damodhar Reddy
Thungon, Shri Prem Khandu
Tirkey, Shri Pius
Tripathi, Shri Kamalapati
Tudu, Shri Manmohan
Tur, Shri L. S.
Tytler, Shri Jagdish
Uike, Shri Chhotelal
Vairale, Shri Madhusudan
Venkataraman, Shri R.
Velu, Shri A. M.
Venkatasubbaiah, Shri P.
Verma, Shri Chandradeo Prasad
Verma, Shri Jai Ram
Verma, Shri R. L. P.
Verma, Shri Raghunath Singh
Vishwa Nath Pratap Singh. Shri
Vyas, Shri Girdhari Lal
Wasnik, Shri Balkrishna Ramchandra
Yadav, Shri Chandrajit
Yadav, Shri D. P.
Yadav, Shri Ram Singh
Yadav, Shri Subhash Chandra
Yadav. Shri Vijay Kumar
Yazdani, Shri Golam
Yellaiah, Shri Nandi
Yusuf, Shri M.
Zail Singh, Shri
Zainal Abedin, Shri
Zainul Basher, Shri

NOES

NIL

MR. SPEAKER: The result** of the Division is: Ayes: 421; Noes: Nil.

The Ayes have it; The Ayes have it. The Motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

The Motion was adopted.

Clauses 2 and 1 were added to the Bill.

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill. . .

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं, "कि विधेयक को पास किया जाय ।"

MR. SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill be passed."

**The result of this division applies to each of the clauses, 2 and 1 separately.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Mr. Speaker, Sir, I have heard the speeches with rapt attention but I regret to say that no reference is made to the tribals particularly in North-Eastern region, people in Nagaland, Mizoram, Arunachal Pradesh and Tripura. The remoteness, lack of communication, lack of economic activities and development programmes and the dire poverty that I have seen during my last tour in that area would upset anybody. The situation in that area is very explosive and the foreign agencies are making hay while the sun shines. It is about time that government took care and paid attention to the tribals in the North-eastern region who have been neglected during the thirty-two year long rule here.

Sir, the Harijans are in a very bad shape....

16.16 hrs.

[SHRI TRIDIB CHAUDHURI *in the Chair*].

Mr. Bhola Paswan Shastri is not a CPM; he is not a communist at all. He had been to West Bengal. He has expressed it in very clear language that since the Left Front Government came into power in West Bengal what has been done for Harijans in West Bengal has no parallel in this country. He has given a complete certificate for it. Our harijan friends and scheduled tribes people live on land. The tribals live on forests. Now they have been deprived of making a living, securing their livelihood from the forest resources. I have been telling this House repeatedly that you will have to give some alternative source of livelihood to the tribals, but that has not been done at all. Land reform in its true sense and in the genuine sense of the term has not been done. Reservation of seats and all this would be only a lip-service and this is not going to take them anywhere unless we can give them what they really require—the land, the value of the inputs and the money for subsistence. These three things are most important. Rao Birendra Singh Ji is sitting here. The ICAR the Laboratory-dancing, never goes to the farmer. Go and ask any scheduled caste or scheduled tribe people how much benefits they have derived out of this ICAR on which you have been spending hundred crores of rupees a year. Sir, I had been a Member of its Governing Body for 2-1/2 years and I am very shocked to see their performance. Kindly find out and make a special survey.

Sir, in the Bill there should be full coverage for those Scheduled Castes and Scheduled Tribes who have become Christians and who have become Muslims, neo-Buddhists and other minorities. The Muslims and other minorities are also the people in another neglected area. I would request the hon. Home Minister to make a note of this and see that their case is not neglected.

SHRI EDUARDO FALEIRO (Mormugao): There is a point of order.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I am speaking on the third reading. I am not yielding.

SHRI EDUARDO FALEIRO: On a point of order you have to yield.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I obey the Chair.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL (Latur): Sir, on a point of order. Rule No. 94 reads like this:

> 'The discussion on a motion that the Bill or the Bill as amended, as the case may be, be passed shall be confined to the submission of arguments either in support of the Bill or for the rejection of the Bill. In making his speech, a member shall not refer to the details of the Bill further than is necessary for the purpose of his arguments which shall be of a general character.'

MR. CHAIRMAN: The Point of order does not arise. The Clauses

[Mr. Chairman]

have already been passed and now it is the final stage. Now it is the Third Reading stage of the Bill. Your Point of order does not arise. You please conclude.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I am concluding, Sir; only educate the hon. Member that in the Third Reading I can cover such areas which have not been covered already. I conclude to oblige you, Sir.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं । इस विधेयक के समर्थन में हिन्दुस्तान के तमाम लोगों ने अपनी आवाज लगाई है, वे हिन्दू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, सब ने तहेदिल से इस विधेयक का समर्थन किया है – यहां भी और इस सदन के बाहर भी । ऐसी स्थिति में यहां यह कहना कि इस का सारा श्रेय हिन्दुस्तान की प्रधान मंत्री – श्रीमती इंदिरा गांधी को है, यह गलत है . . . (**व्यवधान**) . . . . .यह गलत है ।

मैं समझता हूं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी को, खुद इस स्थिति को कबूल नहीं करना चाहिए । यह पूरी जनता की आवाज है, किसी एक व्यक्ति का करिश्मा नहीं है । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो बिल लाया गया है यह पूरे राष्ट्र की आवाज है और पूरे राष्ट्र के लोगों को इस का श्रेय मिलना चाहिए ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हरिजनों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के लिए केरल की सरकार ने, पश्चिम बंगाल की सरकार ने और त्रिपुरा की सरकार ने जितना काम किया है, उतना काम कांग्रेस ने 32 साल की अपनी हुकूमत में भी नहीं किया है ।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने हरिजनों एवं आदिवासियों के आन्दोलनों का नेतृत्व किया है और हम आगे भी इन लोगों का नेतृत्व करते रहेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं इस संविधान (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं ।

सभापति महोदय : होम मिनिस्टर ।

श्री जैल सिंह : सम्मानीय सभापति जी, आनरेबिल मेम्बर श्री ज्योतिर्मय बसु ने बहुत कीमती बातें बताई हैं । उन्होंने एक बात तो यह बताई है कि हरिजनों पर उत्तर प्रदेश में, बिहार में. . . . . .

सभापति महोदय : मिनिस्टर साहब, आप बाद में जवाब दे दीजिए । अभी एक मेम्बर को और बोलना है ।

श्री केयूर भूषण ।

श्री केयूर भूषण (रायपुर) : सभापति महोदय, मैं आप को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप ने मुझे बोलने का समय दिया है ।

मैं मध्य प्रदेश से आया हूं जहां पर जनता पार्टी का शासन है, मगर इस चीज को कहने के लिए मैं जरा भी झिझक नहीं रहा हूं कि वहां पर हरिजनों की जो स्थिति है, वह बहुत दयनीय है । हमारे यहां गुरु घासीदास एक महान सन्त हुए हैं । उनके स्मारक के लिए वहां पर जो जमीन एलाट हुई थी, कांग्रेस के राज्य में, ढ़ाई सालों के प्रयत्न के बाद भी वह अभी तक नहीं मिल पाई है । मुझे इस की पूरी जानकारी है क्योंकि मैं हरिजन सेवक संघ का एक लम्बे समय से कार्य करता रहा हूं । वहां जमीन मिलने में काफी कठिनाई हरिजनों को हो रही है और जो जमीनें उन्हें मिली है उन पर भी पूरी तरह से कब्जा नहीं दिया गया है । वहां के हरिजनों की स्थिति बहुत ही दयनीय है और आप को विशेषकर उस प्रदेश की ओर देखना होगा । हमारी प्रधान मंत्री जी की हरिजनों को सुविधाएं देने के बारे में बहुत बड़ी भूमिका रही है, इस बात को मानना पड़ेगा और जो दस साल का मौका इन्होंने और दिया है, उस के लिए वे बधाई की पात्र हैं ।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिन क्षेत्रों में आदिवासी रहते हैं, वहां पर वे लोग तथा हरिजन भाई बंधकों की तरह जी रहे हैं । ऐसे क्षेत्रों की तरफ माननीय मंत्री जी को विशेष ध्यान देना चाहिए और हम सब को यहां मिल कर उन लोगों के लिए कहना चाहिए कि उन के लिए विकास कार्य किए जाएं । हमारे कम्युनिस्ट साथी किसी एक वर्ग की ही बात को न लें बल्कि भारतवर्ष में, जहां पर जातिगत व्यवस्था है वहां जो पिछड़ी हुई जातियां और लोग हैं, उन को विशेष अवसर विकास करने के लिए देने होंगे और इस क्षेत्र में हम सब पूरी तरह से सहयोग करें, जिस से उन लोगों को अपने हक मिल सकें ।

श्री जैल सिंह : सम्मानीय उपसभापति जी, श्री ज्योतिर्मय बसु ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कहीं । उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में जो ट्राइबल एरियाज हैं, हरिजनों पर, आदिम जातियों पर बहुत जुल्म हुए हैं, उन के साथ बहुत बेइंसाफी हुई है । मैं बसु साहब से इस बात के लिए एग्री करता हूं कि पिछले दो सालों में बहुत कुछ हुआ होगा। (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : जैल सिंह जी मैंने 32 साल बोला है, दो साल नहीं बोला है ।

श्री जैल सिंह : मैं श्री ज्योतिर्मय बसु साहब के साथ इस बात के लिए भी इत्तिफाक करता हूं कि बहुत से गरीब लोग ईसाई, बुद्धिस्ट, मास्लम्स का मजहब बदलने की वजह से इस कैटेगरी में नहीं आते । क्योंकि यह स्टेट सबजेक्ट है इसलिए उनके लिए हम प्रान्तीय सरकारों से कहेंगे कि वह बैकवर्ड क्लासिज के लिए कुछ करें । मैं ने तकरीबन सभी गवर्नरों से बात की है और मैंने उन के थ्रू सभी को कंवे कर दिया है कि हरिजनों, गरीबों और वीकर सेक्शंज पर जोरावरों के जो जुल्म हो रहे हैं, उन के साथ जो मारपिटाई की जा रही है । उन के साथ विन्डिक्टिवनेस का सलूक

किया जा रहा है वह फौरन बंद किया जाऐ । अगर यह सब बंद नहीं होता है तो मैं यकीन दिलाता हूं कि यह सरकार जब यह देखेगी कि कहीं गरीबों को नहीं बचाया जा सकता है तो बड़े से बड़ा कदम उठाने में भी कोई गुरेज नहीं करेगी । यह सरकार को एहसास है कि ला एण्ड आर्डर स्टेट सब्जैक्ट है । (व्यवधान)

सभापति जी मैं आप के माध्यम से अपने दोस्तो से प्रार्थना करता हूं कि वे हरिजनो की भलाई की बात सुनने में तो नाराज न हों ।

मैं ज्योतिर्मय बसु का इस के लिये भी बड़ा मशकूर हूं कि उन्होंने यहां यह बता दिया कि उनकी रक्षा के लिए उन को जमीनें देने के लिए ऋण देने के लिए जो सुविधाएं रखी गई है वह उन हरिजन और गरीब भाईयों को नहीं मिलती है इसलिए सरकार को उनको ये सुविधाएं दिलानी चाहियें । मैं कहना चाहता हूं कि प्रान्तीय सरकारों की तरफ से हरिजन कल्याण के लिए बीकर सेक्शनस के लिए जो कारपोरेशन बनाए गये हैं उन को पूरी सहायता दी जायगी और उन के बारे में सरकार पूरा ध्यान रखेगी ।

एक बात उन्होंने कहीं कि पश्चिम बंगाल में जो हरिजनो के लिए किया गया वह कहीं नहीं किया गया । उस के बारे में मैं कुछ नहीं कहता। वह तो सब रिकार्ड में है और हम उस रिकार्ड को भी देखेंगे ।

श्री ज्योतिमय बसु : कुछ नार्थ इस्टर्न रीजन के बारे में भी कहेंगे ।

श्री जैल सिंह : मैंने पहले अपनी तकरीर में इस हाउस में एक बात कहीं है । कि आनरेबल मेम्बर साहेबान ने जो सुझाव दिये है उस सारी डिबेट की कापी मेरी टेबिल पर रहेगी और मैं उन्हें देखूंगा । क्योंकि इस मसले का सम्बन्ध मुझ से है ।

16.30 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair.*]

आनरेबल सी० पी० आई० के मेम्बर ने बड़े जजबात से एक बात कही मैं उसकी कद्र करता हूं ।

हम भी इस में शामिल हैं । लेकिन इसका श्रेय प्राइम मिनिस्टर को नहीं जाना चाहिये यह भी उन्होने कहा मैं कहना चाहता हूं कुदरत या खुदा के साथ आप मुकाबला नहीं कर सकते है । उनको तो इसका श्रेय चला ही गया है । आपको भी मौका मिला था और आप भी ये सारी बातें करवा सकते थे । लेकिन आप ने नहीं करवाई अढ़ाई साल आप हम लोगों को गालियां देते रहे । हमारे दोस्त थे हमारे साथ थे लेकिन उधर चले गए थे । वे चाहते तो इसका श्रेय चौधरी साहब को दिला देते या श्री मोरारजी भाई को दिला देते हमें क्या नुकसान था ? लेकिन हमें ही उन्होंने इसका श्रेय दिलाना था और दिलाया है ।

(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Whatever is said without my permission, should not be recorded.

श्री जैल सिंह : मैंने पहले भी प्रार्थना की थी सम्मानीय विरोधी दलों के नेताओं का में बड़ा सत्कार करता हूं बड़ी इज्जत उनको देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : जरुरत से ज्यादा करने लगे हैं ।

श्री जैल सिंह : उनकी बात को मैं बड़े ध्यान से सुनता हूं हम सब ट्रेजरी बैंचिज के लोग सुनते है लेकिन उनको भी जरा फराखदिली से हमारी बातो को सुनना चाहिए । आपको मालूम होगा कि जब श्री मोरारजी भाई प्राइम मिनिस्टर थे और आनरेबल मेम्बर बहुत से जो आज उन बैंचों पर बैठे हुए हैं वे तब मिनिस्टर थे और तब बिहार में हरिजनों को जिन्दा जला दिया गया था उनको गोली मार दी गई थी और तब तक अकेली श्रीमती इंदरा गांधी जिन के पास कोई सत्ता नहीं थी और जिन के खिलाफ मुकदमे ही मुकदमे चल रहे थे वहां गई थीं और लोगों के साथ उन्होंने अपनी सहानुभूति प्रकट की थी । मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं । मैं तो सिर्फ इतनी ही प्रर्थना अपने दोस्तो से करना चाहता हुं कि अपने गुनाह देखने के लिए किसी गैर की आंख चाहिये ।

MR. SPEAKER: Before I put the motion that the Bill be passed to the vote of the House, this being a Constitution (Amendment) Bill, voting has again to be by division. Let the lobbies be cleared.

The lobbies have been cleared.

The question is:

"That the Bill be passed."

The Lok Sabha divided:

**Not recorded.

Division No. 3] [16.34 hrs.

AYES

Abbasi, Shri Kazi Jalil
Abdul Samad, Shri
Acharia, Shri Basudeb
Agarwal, Shri Satish
Ahmed, Shri Mohd. Asrar
Ahmad, Shri Md. Kamaluddin
Ajit Pratap Singh, Shri
Alluri, Shri Subhash Chandra Bose
Amarender Singh, Shri
Anand Singh alias Annubhaiya, Shri
Anbarasu, Shri Era
Ansari, Shri Shafique-llah
Ansari, Shri Z. R.
Anthony, Shri Frank
Anuragi, Shri Godil Prasad
Anwar Ahmed, Shri
Appalanaidu, Shri S.R.A.S.
Arakal, Shri Xavier
Arjunan, Shri K.
Arunachalam, Shri M.
Ashfaq Hussain, Shri
Athare, Shri Chandrabhan Balaji.
Azad, Shri Bhagwat Jha
Azad, Shri Gulam Nabi
Aziz Imam, Shri
Baitha, Shri D.L.
Bajpai, Dr. Rajendra Kumari
Balan, Shri A.K.
Balanandan, Shri
Baleshwar Ram, Shri
Banatwala, Shri G.M.
Bansi Lal, Shri
Banwari Lal, Shri
Barman, Shri Palas
Barot, Shri Maganbhai
Barot, Shri A.E.T.
Barve, Shri J.C.
Basu, Shri Chitta
Behara, Shri Rasa Behari
Bhagat, Shri Baliram
Bhagat, Shri H.K.L.
Bhagwan Dev, Shri
Bhakta, Shri Manoranjan
Bhardwaj, Shri Parsram
Bhatia, Shri R.L.
Bhattacharya, Shri Sushil Kumar
Bhikhabhai, Shri
Bhim Singh, Shri
Bhoi, Dr. Karupa Sindhu
Bhole, Shri R.R.
Bhoye Reshma Motiram, Shri
Bhuria, Shri Dileep Singh
Bijendra Pal Singh, Shri
Birbal, Shri
Birender Singh Rao, Shri
Biswas, Shri Ajoy
Boddepalli, Shri Rajagopala Rao
Bosu, Shri Jyotirmoy
Butta Singh, Shri
Chakraborty, Shri Satyasadhan
Chakradhari, Shri
Chandra Pal Singh, Shri
Chandra Shekhar Singh, Shri
Chandrakar, Shri Chandulal
Chandrasekharappa, Shri T. V.
Charan Singh, Shri
Charanjit Singh, Shri
Chatterjee, Shri Somnath
Chaturbhuj, Shri
Chaturvedi, Shrimati Vidyavati
Chaudhary, Shri R. Motibhai
Chaudhuary, Shri Tridib
Chavan, Shri Shankarrao Bhaurao
Chavan Shri Y.B.
Chavda, Shri Ishwarbhai Khodabhai
Chawdhury, A. B. A. Ghani
Chennupati, Shrimati Vidya
Chingwang, Shri
Chiranji Lal Sharma, Shri
Choubey Shri Narayan
Choudhari, Shri K.B.
Chaudhari, Shrimati Usha Prakash
Chouhan, Shri Fatebhanu Singh

Chowdhary, Shri Saifuddin
Dabhi, Shri Ajitsinh
Daga, Shri Mool Chand
Dalbir Singh, Shri
Dalbir Singh, Shri
Damor, Shri Somjibhai
Dandavate, Prof. Madhu
Dandavate, Shrimati Pramila
Das, Shri A.C.
Das, Shri R.P.
Dennis, Shri N.
Deo, Shri K.P. Singh
Deo, Shri V. Kishore Chandra S.
Desai, Shri B.V.
Devarajan, Shri B.
Devinder Singh, Shri
Dhandapani, Shri C.T.
Dhavamgaj Singh, Shri
Digvijay Sinh, Shri
Dogra, Shri G.L.
Doongar Singh, Shri
Dorai Sebastian, Shri S.A.
Dubey, Shri Bindeshwari
Dubbey, Shri Ram Nath
Ekka, Shri Christopher
Era Mohan *alias* Ram Mohan R., Shri
Faleiro, Shri Eduardo
Fernandes, Shri George
Fernandes, Shri Oscar
Gadgil, Shri V.N.
Gadhavi, Shri Bheravadan K.
Gaekwad, Shri R.P.
Gaikwad, Shri Udaysingrao
Gamit, Shri Chhitubhai
Gandhi, Shrimati Indira
Gandhi, Shri Sanjay
Gehlot, Shri Ashok
Ghorpade, Shri R.Y.
Ghosh, Shri Niren
Giri, Shri Sudhir Kumar
Giriraj Singh, Shri
Goel, Shri K.K.
Gohil, Shri G.B.
Gomango, Shri Giridhar
Gopalan, Shrimati Suseela
Goswami, Shrimati Bibha Ghosh
Gounder, Shri A. Senapathi
Gouzagin, Shri
Gowda, Shri D.M. Putte
Gufran Azam, Shri
Gulsher Ahmed, Shri
Gupta, Shri Indrajit
Gurbinder Kaur, Shrimati
Gurcharan Singh, Shri
Hakam Singh, Shri
Halder, Shri Krishna Chandra
Hannan Mollah, Shri
Harikesh Bahadur, Shri
Hasda, Shri Matilal
Horo, Shri Nirel Enem
Imbichi Bava, Shri E.K.
Jaffer Sharief, Shri C.K.
Jagjivan Ram, Shri
Jagpal Singh, Shri
Jai Narayan, Shri
Jaiba, Smt. Rane Sirdessai Sanyogita
Jain, Shri Bhiku Ram
Jain, Shri Virdhi Chand
Jaydeep Singh, Shri
Jena, Shri Chintamani
Jethmalani, Shri Ram
Jha, Shri Kamal Nath
Jharkhande Rai, Shri
Jitendra Prasad, Shri
Kailash Pati, Shrimati
Kalanidhi, Shri A.
Kalpnath Shankar, Shri
Kamakshaiah, Shri D.
Kamal Nath, Shri
Kamla Kumari, Shrmati
Kandaswamy, Shri M.
Karan Singh, Dr.

Karma, Shri Lachman
Karunanithi Thazhai, Shri
Kashirsagar, Shrimati Kesharbai
Kashyap, Shri Jaipal Singh
Kaul, Shrimati Sheila
Kaushal, Shri Jagannath
Keyur Bhusan, Shri
Khan, Shri Arif Mohammad
Khan, Shri Ghayoor Ali
Khan, Shri Malik M.M.A.
Khan, Shri Zulfiquar Ali
Kidwai, Shrimati Mohsina
Kochack, Shri Ghulam Rasool
Kodiyan, Shri P.K.
Krishna Pratap Singh, Shri
Krishnan, Shri G.Y.
Kuchan, Shri Gangadhar S.
Kulandaivelu, Shri V.
Kunhambu, Shri K.
Kunwar Ram, Shri
Lakkappa, Shri K.
Lakshmanan, Shri G.
Laskar, Shri Nihar
Lawrence, Shri M.M.
Madhukar, Shri Kamla Mishra
Mahabir Prasad, Shri
Mahajan, Shri Vikram
Mahajan, Shri Y.S.
Mahala, Shri R.P.
Mahata, Shri C.R.
Mahendra Prasad, Shri
Maitra, Shri Sunil
Makawana, Shri Narsinh
Mallanna, Shri K.
Mallikarjun, Shri
Mallu, Shri A.R.
Mandal, Shri Sanat Kumar
Mani, Shri K. B. S.
Manphool Singh, Shri
Meena, Shri Ram Kumar
Mehta, Shri Ajit Kumar
Mehta, Dr. Mahipatray M.
Mhalgi, Shri R. K.
Mirdha, Shri Nathu Ram
Mishra, Shri Hari Nath
Mishra, Shri Ram Nagina
Misra, Shri Satyagopal
Mohammed Ismail, Shri
Mohanty, Shri Brajamohan
Mohite Shri Yashawantrao
More, Shri Ram Krishna
Motilal Singh, Shri
Mukherjee, Shrimati Geeta
Mukherjee, Shri Samar
Mukhopadhyaya, Shri Anand Gopal
Mundackal, Shri George Joseph
Murthy, Shri Kusuma Krishna
Murthy, Shri M. Rajashekara
Murthy, Shri M. V. Chandrashekhara
Murgian, Shri S.
Muttemwar, Shri Vilas
Nadar, Shri A. Neelalohithadasan
Nagaratnam, Shri T.
Naidu, Shri P. Rajagopal
Naik, Shri Surupsing H.
Naikar, Shri D. K.
Nair, Shri B. K.
Nanje Gowda, Shri H. N.
Narayana, Shri K. S.
Naval Kishore Sharma, Shri
Nayak, Shri Mrutyanjaya
Negi, Shri T. S.
Netam, Shri Arvind
Ngangom Mohendra, Shri
Nihal Singh, Shri
Nikhra, Shri Rameshwar
Nitya Nanda Misra, Shri
Odedra, Shri Maldevji M.
Oraon, Shri Kartik
Pahadia, Shri Jagannath
Palaniappan, Shri C.
Pandey, Shri Kedar
Pandey, Shri Krishna Chandra
Panika, Shri Ram Pyare
Parashar, Prof. Narain Chand

Pardhi, Shri Keshaorao
Parmar, Shri Hiralal R.
Parthasarathy, Shri P.
Parulekar, Shri Bapusaheb
Paswan, Shri Ram Vilas
Patel, Shri Ahmed Mohammed
Patel, Shri Amrit
Patel, Shri C. D.
Patel, Shri Shantubhai
Patel, Shri U. H.
Pathak, Shri Anand
Patil, Shri Balasaheb Vikhe
Patil, Shri Shankarrao
Patil, Shri Shivraj V.
Patil, Shri A T.
Patil, Shri Uttamrao
Patil, Shri Vasantrao
Patil, Shri Veerendra
Patil, Shri Vijay N.
Patnaik, Shri Janki Ballav
Pattuswamy, Shri D.
Penchalaiah, Shri
Phulwariya, Shri Virda Ram
Pilot, Shri Rajesh
Poojary, Shri Janardhana

Prabhu, Shri R.
Pradhan, Shri Amar Ray
Pradhani, Shri K.
Prasanna, Shri S. N.
Pushpa Devi Singh, Kumari
Pullaiah, Shri Darur
Qazi Saleem, Shri
Quadri, Shri S. T.

Raghavan, Shri V. S. Vijaya
Rahi, Shri Ram Lal
Rahim, Shri A. A.
Rai, Shrimati Sahodarabai
Rajamallu, Shri K.
Rajan, Shri K. A.
Rajda, Shri Ratansinh
Rajesh Kumar Singh, Shri
Raju, Shri P. V. G.
Rakesh, Shri R. N
Ram, Shri Ramswaroop
Ramalingam, Shri N. Kudanthai
Ramamurthy, Shri K.
Ramanna Rai, Shri M.
Ramayan Rai, Shri
Ramdhan, Shri Prabhunarayan
Ramulu, Shri H. G.
Ranabir Singh, Shri
Ranga, Shri N. G.
Ranjit Singh, Shri
Rao, Shri Ankineedu Prasada
Rao, Shrimati B. Radhabai Ananda
Rao, Shri Jagannath
Rao, Shri Jalagam Kondaia
Rao, Shri M. Nageswara
Rao, Shri M. S. Sanjeevi
Rao, Shri M. Satyanarayana
Rao, Shri S. B. P. Pattabhi Rama
Rasheed Masood, Shri
Rathawa, Shri Amar Sinh
Rathod, Shri Uttam
Raut, Shri Bhola
Ravani, Shri Navin
Rawat, Shri Harish
Reddy, Shri G. S.
Reddy, Shri G. Narsimha
Reddy, Shri K. Brahmananda
Reddy, Shri K. Obul
Redy, Shri K. Vijay Bhaskara
Reddy, Shri M. Ram Gopal
Reddy, Shri P. Venkata
Riyan, Shri Baju Ban
Rothuama, Dr. R.
Roy, Shri A. K.
Roy, Dr. Saradish

Saha, Shri Gadadhar
Sahi, Shrimati Krishna
Sahu, Shri Narayan
Sajjan Kumar, Shri
Samin Uddin, Shri
Sangama, Shri P. A
Sathe, Shri Vasant
Satish Prasad Singh, Shri

Satya Deo Singh, Prof.
Sawant, Shri T. M.
Sayeed, Shri P. M.
Selvaraju, Shri N. B. E.
Sethi, Shri Arjun
Sethi, Shri P. C.
Shailani, Shri Chandra Pal
Shaktawat, Prof. Nirmala Kumari
Shakya, Shri Ram Singh
Shakyawar, Shri Nathuram
Shamanna, Shri T. R.
Shantaram, Shri
Sharma, Shri K. C.
Sharma, Shri Munder
Sharma, Shri Nand Kishore
Sharma, Dr. Shankar Dayal
Sharma, Shri Vishwa Nath
Shastri, Shri Dharam Dass
Shastri, Shri Harikishan
Shastri, Shri Ramavatar
Shingda Shri D. B.
Shiv Shankar, Shri P.
Shivendra Bahadur Singh, Shri
Shivkumar Singh, Shri Thakur
Shukla, Shri Vidya Charan
Sidnal, Shri S. B.
Singaravadivel, Shri S.
Singh, Shri B. D.
Singh, Shri C. P. N.
Singh, Shrimati Madhuri
Sinha, Shri Dharam Bir
Sinha, Shrimati Ramdulari
Sivaprakasam, Shri D. S. A.
Solanki, Shri Babu Lal
Solanki, Shri Natvarsinh
Sontosh, Mohan Dev, Shri
Sparrow, General R. S.
Sreenivasa Prasad, Shri V.
Subbe, Shri P. M.
Sukhadia, Shri Mohanlal
Sukhbuns Kaur, Shrimati
Sunder Singh, Shri
Suraj Bhan, Shri
Surya Narayan Singh, Shri
Suryawanshi, Shri Narsing Rao
Swami, Shri K. A.
Swamy, Dr. Subramaniam
Syed, Shri Masudal Hossain

Tapeshwar Singh, Shri
Tariq Anwar, Shri
Tayeng, Shri Sobeng
Tayyab Husain, Shri
Tewari, Shri Chandra Bhal Mani
Tewari, Shri Narayan Datt
Tewary, Prof. K. K.
Thorat, Shri Bhausaheb
Thummalapalli, Shri Damodar Reddy
Thungor, Shri Prem Khandu
Tirkey, Shri Pius
Tripathi, Shri Kamalapati
Tudu, Shri Manmohan
Tur, Shri L. S.
Tytler, Shri Jagdish

Uike, Shri Chhotelal

Vairale, Shri Madhusudan
Venkataraman, Shri R.
Velu, Shri A. M.
Venkatasubbaiah, Shri P.
Verma, Shri Chandradeo Prasad
Verma, Shri Jai Ram
Verma, Shri Raghunath Singh
Vishwa Nath Pratap Singh, Shri
Vyas, Shri Girdhari Lal

Wagh, Dr. Pratap
Wasnik, Shri Balkrishna Ramchandra

Yadav, Shri Chandrajit
Yadav, Shri D. P.
Yadav, Shri R. P.
Yadav, Shri Ram Singh
Yadav, Shri Subhash Chandra
Yadav, Shri Vijay Kumar
Yazdani, Shri Golam
Yellaiah, Shri Nandi
Yusuf, Shri M.

Zail Singh, Shri
Zainal Abedin, Shri
Zainul Basher, Shri

NOES

Nil

MR. SPEAKER: The result of the Division is Ayes 423; Noes Nil.

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting.

The Bill is passed by the requisite majority in accordance with the provisions of Article 368 of the Constitution.

The motion was adopted.

16.48 hrs.

PAYMENT OF BONUS (AMENDMENT) BILL

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION AND LABOUR (SHRI J. B. PATNAIK): Sir, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Payment of Bonus (Amendment) Act, 1977, be taken into consideration."

It is not a controversial Bill. It is as non-controversial as the preceding Bill which was under the consideration of the House. This Bill is meant for validating the ordinance of 1979 and I wish that the House should pass this Bill before long, so that this ordinance may not lapse. Otherwise, it will create difficulties for the workers who have not been paid bonus under the ordinance.

The limited purpose of this Bill is to validate the ordinance of 1979. According to this ordinance, bonus is payable for the accounting year 1978. Payments should already have been made to large sections of workers. Payments are yet to be made to the remaining sections of workers. Unless this Bill is passed, the remaining sections of the workers who are to be paid would remain unpaid or would be subjected to discriminatory treatment.

With these words, I move the Bill for the consideration of this House.

MR. SPEAKER: Motion moved:

> "That the Bill further to amend the Payment of Bonus (Amendment) Act, 1977, be taken into consideration".

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष महोदय मैं बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । माननीय मंत्री जी ने आर्डिनेन्स के समर्थन में जिस बयान को यहां पर दिया और उसके पहले इस सदन के सामने रखा था उसमें इस विधेयक की क्या जरूरत पड़ी इसके विषय में जिक्र है । असल में इस विधेयक का और उस आपातकाल का बहुत गहरा रिश्ता है । इसकी शुरुआत असल में 25 सितम्बर 1975 को हुई थी जब उस समय के बोनस के कानून में संशोधन किया गया था एक अध्यादेश के जरिए से और बरसों के संघर्ष से मजदूरों ने जिस अधिकार को हासिल किया था उस पर कुठाराघात करने का काम किया गया । लगातार दो साल तक वह अध्यादेश और उसके बाद 1976 में कानून में किया हुआ संशोधन जारी रहा । 1977 में जब नई सरकार बनी तो उसने आपातकाल में मजदूरों द्वारा खोए हुए अधिकारों को फिर से वापिस लौटाने का काम किया था । (व्यवधान) ।

एक माननीय सदस्य : आपने सरकार क्यों छोड़ी ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, इस समय हम बोनस के विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं हमने मंत्रिमण्डल क्यों छोड़ा इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं । अगर माननीय सदस्य उसकी चर्चा करना चाहेंगे तो वह चर्चा करने के लिए भी हम तैयार हैं हमें कोई आपत्ति नहीं है । मगर इस समय हम इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं । (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Order, please order. Take your seats. Let the hon. member speak.

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अगर मेरा समय इस तरह से लिया जाता है तो वह समय मुझे मिलना चाहिए ।

MR. SPEAKER: Please be concise. There is very little time left. We have got one more Bill.

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आज इस विधेयक के माध्यम से उन अधिकारों को फिर से लौटाने का जो इन्तजाम किया जा रहा है उसकी हमको खुशी है । सदन में सभी तरफ से इसको समर्थन है और विशेषकर उन्हीं लोगों ने आज इस विधेयक